₹ 10
www.kewalsachtimes.com
जुलाई 2026

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO-131729, POSTAL REG. NO.:-PS-78

केन-बेतवा का संघर्ष :

टूटती सांसें, सुलगते सवाल

मुआवजे और पुनर्वास पर कब जागेगा प्रशासन ?

जन-जन की आवाज है केवल सच

केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalsachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
खबर वहीं, जो केवल सच हो
Mob.: 9431073769, 9308815605

केवल सच TIMES

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM UPI
G Pay Paytm

www.kewalsach.com www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

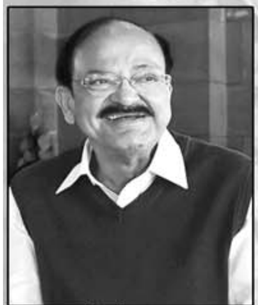
एम. वेंकैया नायडू
01 जुलाई 1949

अखिलेश यादव
01 जुलाई 1973

हरभजन सिंह
03 जुलाई 1980

स्व० रामविलास पासवान
05 जुलाई 1946

एम.एस. धोनी
07 जुलाई 1981

कैलास खेर
07 जुलाई 1973

सौरभ गांगुली
08 जुलाई 1972

सुखवीर सिंह बादल
9 जुलाई 1962

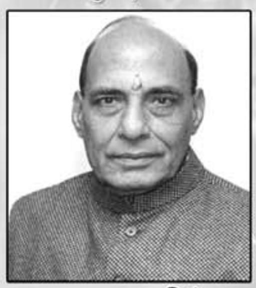
राजनाथ सिंह
10 जुलाई 1951

सुनिल गवास्कर
10 जुलाई 1949

रवि किशन
17 जुलाई 1971

प्रियंका चोपड़ा
18 जुलाई 1982

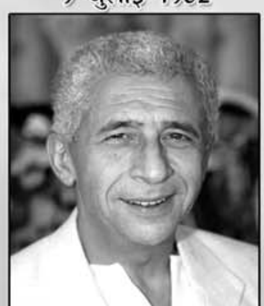
नसरूद्दीन शाह
20 जुलाई 1950

मल्लिकार्जुन खड़गे
21 जुलाई 1942

स्व० अनंत कुमार
22 जुलाई 1959

हिमेश रेशमिया
23 जुलाई 1973

पंकज आडवाणी
24 जुलाई 1985

उद्धव ठाकरे
27 जुलाई 1960

संजय दत्त
29 जुलाई 1959

सोनू निगम
30 जुलाई 1973

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Cover Page	3,00,000/-	N/A
Back Page	1,00,000/-	65,000/-
Back Inside	90,000/-	50,000/-
Back Inner	80,000/-	50,000/-
Middle	1,40,000/-	N/A
Front Inside	90,000/-	50,000/-
Front Inner	80,000/-	50,000/-

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

संकट में है बिहार

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

बिहार की राजनीति लट्टू की तरह नाचती दिखती है। 1990 से लेकर 2005 तक लालू-राबड़ी की सरकार में विकास कागजों पर ही ज्यादा दिखता था और भ्रष्टाचार, अपराध को प्रमुखता से जगह मिलती थी और न्यायालय भी बिहार को जंगलराज की उपाधि दी थी। 2005 से 2025 तक नीतीश कुमार एवं अन्य की संयुक्त सरकार बनी और विकास की गति तो मिली लेकिन इस सरकार में विलंब करके टेंडर की राशि को कई गुणा बढ़ाकर पूरा करके भ्रष्टाचार को इस कदर बढ़ाया गया कि बिहार सरकार के पास फंड का आभाव से प्रदेश में संकट का बादल मंडराने लगा है। लालू - राबड़ी की सरकार में राजनीति सिस्टम पर हावि था तो नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही का मनोबल इतना बढ़ गया कि अपने चैम्बर में विधायक को हड़काते हुए विडिओ वायरल में नजर आये। पुलिसिया एवं प्रशासनिक आतंक दिन - प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तथा आमजनता को बंधुआ मजदूर समझकर भगा दिया जाता है। सत्ता के अहंकार में बिहार संकट के दौर में पहुंचता जा रहा है। 1990 के दौर से भी ज्यादा खराब वातावरण बिहार में संकट में डालता जा रहा है। हत्या, गैंगरेप के साथ पुलिस की दादागिरी की वजह से आमजनता का विश्वास सरकार से उठता जा रहा है। विपक्ष की कमजोर रवैये एवं सत्ता का विरोध कर पाने में विफल होने की वजह से भी सत्ता अहंकारी हो गयी और बिहार संकट में जाने के बाद भी अंधभक्ति में मशगूल होकर खास जनता सत्ता के तलवे चाट रही है जिसके कारण बिहार संकट से कैसे बाहर निकलेगा? बिहार के संकट बढ़ने से 13 करोड़ जनता प्रभावित होगी और इसका प्रभाव लंबे समय तक चलता रहेगा।

बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है और इसके अतित पूरे विश्व को शांति का संदेश देता रहा है तथा रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका का निर्वहण करता रहा है। महापुरूष ही नहीं भगवान भी इस धरा पर अवतरित हुए हैं और पूरा विश्व लोकतंत्र के लिए बिहार का सम्मान करता है। 1947 के पहले वाला बिहार और आजादी के बाद का बिहार धीरे-धीरे संकट में फंसता चला गया और 2026 में बिहार के लोग रोजगार एवं उच्च शिक्षा सहित बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी दूसरे प्रदेश पर ही आश्रित हैं। 1985 के बाद बिहार में भ्रष्टाचार का वर्चस्व ऐसा बढ़ता चला गया कि बाढ़ हो सुखाड़ हो, जनता को राहत मिले या नहीं लेकिन विभाग के अधिकारी, बाबू और राजनेताओं का घर का खजाना भर जाता है। भ्रष्टाचार के मामले में कोई एक पार्टी ही जिम्मेवार नही है बल्कि जिसकी भी सत्ता रही उसने बिहार के सरकारी खजाने को जमकर लूटा जिसकी वजह से बिहार का वास्तविक एवं समुचित विकास नहीं हो सका। सत्ता पर काबिज रहने के लिए बार-बार सरकार की अदला-बदली हुई लेकिन बिहार की जनता के हांथ सिर्फ अगला चुनाव ही लगा। बिहार में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और सरकारी धन का दुरुपयोग प्रगति को धीमा कर दिया और गरीबों को उचित लाभ प्राप्त करने से रोक दिया है। प्रदेश की गरीबी बिहार में सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करने वाले सबसे गंभीर मुद्दों में से प्रमुख है साथ हीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। वहीं राजनीतिक पार्टियां सिर्फ सरकार बनी एवं बची रहे के जुगाड़ में रही जिसके वजह से बिहार में संकट का बादल हमेशा मंडराता रहता है। प्रदेश में सरकारी उदासीनता की वजह से नीजी विद्यालयों का जाल पूरे प्रदेश में फैल चुका है और खुद सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित राजनेताओं को अपने सरकार के शिक्षा व्यवस्था कारगर नहीं लगता जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों में वहीं बच्चे जाते हैं जिनका नामांकन नीजी स्कूलों में उनके अभिभावक नहीं करा सकते। राज्य में शिक्षा का स्तर निम्न है और निरक्षरता की दर बहुत अधिक है। शिक्षा तक पहुंच इस क्षेत्र की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण है। अपर्याप्त शिक्षा प्रणाली के परिणाम स्वरूप आबादी के पास सीमित कौशल होने के कारण बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है। सरकार ने सरकारी शिक्षा प्रणाली को बहुत उपयोगी बनाने में मशगूल तो है लेकिन बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण सरकारी विद्यालय सिर्फ मनोरंजन का केन्द्र बनकर रह गया और जातिवाद के कारण इसकी स्थिति दिनों-दिन लचर होती जा रही है। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद एक के बाद एक निर्माण कार्य एवं विभिन्न क्षेत्रों में संविदा पर काम मिलने लगा लेकिन जिस अनुपात में बेरोजगारी है उसके अनुसार वह संख्या काफी कम है। बिहार राज्य से लोगों के पलायन का मुख्य कारण यहाँ रोजगार तथा अवसरों की घोर कमी है और रोजगार की कमी यहाँ पर उद्योगों का न होना है। बिहार में आधारभूत संसाधनों की कमी को दूर करना तथा उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उचित एवं आकर्षक नीति की ठोस आवश्यकता है। सरकारी सेवा से कहीं ज्यादा नीजी क्षेत्र में रोजगार मिलता है लेकिन बढ़ते अपराध एवं भ्रष्टाचार के कारण छोटे एवं मंझोले स्तर के उद्योग नहीं है और बिहार के विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में स्थानीय उद्योग को जिला प्रशासन एवं जिला उद्योग विभाग की लापरवाही एवं उदासीनता की वजह से उनको प्रोत्साहन नहीं मिला और मोटा कमीशन के बाद ही सरकार का सहयोग मिल सकता है की सोच के कारण ही लोग दूसरे राज्य में जाकर कार्य करने को मजबूर हैं। केन्द्र बिहार की खासियत और समस्याओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाये। एक ही तरह की योजना से पूरे देश का विकास संभव नहीं है। क्षेत्रीय असमानता रहेगी तो सिर्फ बिहार ही नहीं कई अन्य राज्यों का भी विकास नहीं हो पाएगा। बिहार का इन क्षेत्रों में विकास के लिए पहल होगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश का संकट कम होगा और बिहार खुशहाल बन सकता है। ऐतिहासिक स्थल, कृषि योग्य भूमि, उपजाऊ जमीन, मेहनती लोग, योग्य युवा और बिहारियों की इच्छा शक्ति। प्रदेश की जनसंख्या घनत्व, बाढ़ और सुखाड की समस्या भी काफी जटिल है और इसके लिए योजनाएं बनाते समय इन बातों का प्रमुखता से ध्यान रखते हुए इसका समाधान करना होगा। लंबे समय से बिहार को विशेष दर्जा का मांग किया जा रहा है और झारखंड के अलग हो जाने की वजह से बिहार प्रदेश के संसाधन का घोर आभाव है और अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाये तो हम अपने देश के विभिन्न राज्यों को पीछे छोड़ सकते हैं। साथ ही भूमि विवाद के कारण भी प्रदेश में घोर सकंट है भूमि वितरण में असमानता विकास में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है। कृषि का समुचित विकास भी बिहार में संकट के दौर से गुजर रहा है। ग्रामीण बिहार में भूमि ही प्राथमिक संपत्ति और आजीविका का केन्द्र बनी हुई है। कुछ लोग सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों को, विशेष रूप से 1980 और 1990 के दशक के दौरान, आर्थिक गिरावट का कारण मानते हैं जबकि इसके 21 वर्षों में बिहार को संकट से निकालने की कोशिश तो हुई लेकिन कागजी भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की वजह से बिहार घोर संकट के दौर से गुजर रहा है और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के बाद ही संकट से मुक्ति मिल सकती है अन्यथा...।

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

वर्षः- 16, अंकः- 181 माहः- जुलाई 2026 रू. 10/-

Editor

Brajesh Mishra 9431073769
6206889040
8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Principal Editor

Arun Kumar Banka 7782053204
Nilendu Kumar Jha 9431810505

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad 9308815605

General Manager (Advertisement)

Manish Kamaliya 6202340243
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra 8873004350
S. N. Giri 9308454485

Asst. Editor

Mithilesh Kumar 9934021022
Sashi Ranjan Singh 9431253179
Rajeev Kumar Shukla 7488290565

Sub. Editor

Arbind Mishra 6204617413
Prasun Pusakar 9430826922

Bureau Chief

Sanket kumar Jha 7762089203

Bureau

Sridhar Pandey 9852168763
Sonu Kumar 8002647553

Photographer

Mukesh Kumar 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 9868700991

झारखण्ड हेड

ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 9433567880
9339740757

मध्यप्रदेश हेड

अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

छत्तीसगढ़ हेड

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड

निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

उत्तराखण्ड हेड

आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड

आवश्यकता है

गुजरात हेड

आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

पंजाब हेड

आवश्यकता है

हरियाणा हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

उड़ीसा हेड

आवश्यकता है

आसाम हेड

आवश्यकता है

हिमाचल हेड

आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू दिल्ली-110052
मो०- 9868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 9433567880, 9339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय त्तल,
फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 9308815605

मध्यप्रदेश कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार पाठक
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
मो०- 8109932505,

विशेष प्रतिनिधी

भारती मिश्रा 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,
मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

जून 2026

आरक्षण

मिश्रा जी,

जून 2026 अंक में आपका संपादकीय सही मायने में देश की जनता का आंख खोलता नजर आ रहा है। आपका संपादकीय **''खतरे में है आरक्षण''** शीर्षक हीं अपने आप में लोगों का ध्यान बरबस अपनी ओर खिंचता है। इस विषय पर राजनेता एवं विभिन्न पार्टियां भी कुछ भी बोलने से परहेज करती है वैसे में आपका यह आलेख समाज को जागरूक करने के साथ सरकार को आईना दिखा रहा है। आरक्षण सच में देश के विकास में बाधक है और राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से इसके असली हकदार को इसका लाभ भी नहीं मिलता और सामाजिक भेदभाव भी इसी वजह से बढ़ता जा रहा है।

● **कमल पाठक, रेलवे कॉलोनी, इंदौर एम.पी**

कांग्रेस

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स, पत्रिका के जून 2026 अंक में पृष्ठ संख्या 19-20 पर प्रकाशित खबर ''TMC और NCP को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए?'' में शिवसेना के नेता संजय राउत की बात को गंभीरता पूर्वक लिखा गया है। पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र में भाजपा की मिली भयंकर जीत एवं पश्चिम बंगाल में TMC की हार के साथ महाराष्ट्र उमें NCP की करारी हार के बाद कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए की बात को राजनीतिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। TMC और NCP पहले कांग्रेस के पार्ट थी और अब एक होती है तो कांग्रेस मजबूत होगी। अच्छी खबर।

● **प्रदीप सिन्हा, अस्सी घाट, बनारस, यूपी**

शिकंजा

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स पत्रिका भी बेबाक खबरों को पाठकों के बीच रखता है। जून 2026 में शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला की संयुक्त खबर **''ईडी का शिकंजा या राजनीतिक जाल?''** में बिहार की राजनीतिक षडयंत्र एवं प्रशासनिक चूक पर धारदार खबर को पूरे प्रमाण के साथ लिखा है जो पठनीय एवं चिंतनीय है। बिहार में दलाल रिशु श्री के साथ आईएएस संजीव हंस, संतोष मल्ल, दीपक कुमार, आन्द किशोर सहित दर्जन भर अधिकारियों के साथ संबंध की खबरें आम जनमानस के बीच है लेकिन सरकार सिर्फ जांच के नाम पर दिखावा ही कर रही है। दमदार खबरों को लिखने के लिए दोनों पत्रकार बधाई के पात्र हैं।

● **कौशल सिंह, करोल बाग, नई दिल्ली**

एनकाउंटर

संपादक महोदय,

आपकी पत्रिका का दमदार तेवर की वजह से सरकार एवं समाज में अलग पहचान रखता है। केवल सच टाइम्स पत्रिका के जून 2026 अंक में पत्रकार अमित कुमार की खबर **''भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर?''** में सम्राट चौधरी के बेलगाम पुलिस की खूनी करततू को पूर्ण बेबाकी से लिखा है। पुलिस एवं प्रशासनिक गतिविधियों पर सटीक खबर को पूरे विस्तार से पाठकों के समक्ष रखते हुए सरकार से भी कई सवाल पूछे हैं। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटते ही बिहार की छवि फिर से पुराने अतित की ओर लौटती दिख रही है। खबर ने सरकार के साथ पुलिस की छवि पर सवाल उठायें है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि केवल सच टाइम्स अपने तेवर में खबर लिखता है।

● **जितेन्द्र सिंह, अशोक नगर, नई दिल्ली**

पेपर लीक

मिश्रा जी,

मैं केवल सच टाइम्स द्विभाषीय पत्रिका का नियमित पाठक हूं और इसकी दमदार खबरों को बिना पढ़े नींद ही नहीं आती। जून 2026 अंक में अमित कुमार की खबर ''NEET-UG 2026 पेपर लीक'' में नैतिक शिक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ की वजह को पूर्ण बेबाकी के साथ प्रकाशित करना सटीक पत्रकारिता को प्रदर्शित करता है। छात्रों के भविष्य के साथ मजाक कर रही सरकार एवं प्रधानमंत्री का अमृतकाल देश के लिए विषकाल भी बन सकता है। पेपर लीक का मामला बढ़ता ही जा रहा है जिसकी वजह से होनहार छात्रों का भविष्य अंहकार में डूबता जा रहा है और केन्द्र सरकार NTA पर कार्रवाई करने के बजाय छात्रों से ही खेल रहा है।

● **दिनेश राम, मानपुर बाजार, गया**

भरत तिवारी

ब्रजेश जी,

भरत तिवारी की हत्या हुई या एनकाउंटर? यह सवाल देश की जनता जानना चाहती है। हत्या या एनकाउंटर तो बहुत हुए लेकिन भरत तिवारी के मामले ने बिहार सरकार की नींद हराम करके रख दी क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा मुआवजा में हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को उजागर होने से रोकने की एक कार्रवाई है, देखकर भी लोग हैरत में है। भरत तिवारी शहीद हुआ और सम्राट चौधरी की सरकार शर्मसार। इस प्रकरण में देश के भीतर एक बार फिर से आजादी की लड़ाई एवं क्रांतिकारी सोच को बल मिलता दिख रहा है। बिहार की राजनीति में यह पहली दफा है जब किसी की मौत पर पूरा देश में मातम छा गया। भरत भूषण तिवारी को विनम्र श्रद्धांजलि

● **एम.बी. तिवारी, चंदवा, पुलिस लाईन, आरा**

अन्दर के पन्नों में

10

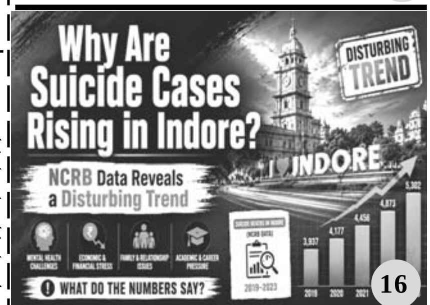

16

22

35

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी

'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

एक नजर

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

e-mail:- kewalsach@gmail.com,

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।

☞
A/C No.	:- 20001817444
BANK	:- State Bank Of India
IFSC Code	:- SBIN0003564
PAN No.	:- AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of
"APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed
Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
Registered Under the Indian Society Act 21, 1880
East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020
Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077
E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com
Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 || 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63
APNA GHAR
Now in the State of Bihar & Jharkhand
Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your
Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence
in the lives of many Sr. Citizens.
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
A/C No. - 0600010202404
Bank Name - United Bank of India
IFSC Code - UTBIOKKB463
Pan No. - AAAAK9339D

● **अमित कुमार**

रामचरितमानस में कहा गया है 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा', लेकिन कलयुग में कह सकते हैं कि 'का हो भैया रामलला के मंदिरों में डाल डालो डाका'।

हां, मतलब जो अभी सुर्खियों में खबर रामलला मंदिर की चल रही है, उसके बाद से देश के करोड़ों रामभक्त आज जो सवाल पूछ रहे हैं रामलला से ही कि 'हे रामलला! का तुम्हरे घर मा भी चोरन के नजर पड़ गए'। क्योंकि अयोध्या के जिस राम मंदिर को बनवाने के लिए साढ़े पांच सौ साल की लड़ाई राम भक्तों ने लड़ी, जिसके लिए न जाने कितने लोग जेल गए, कितनों ने प्राण दे दिए, कितनों की आंखें इंतजार में दुनिया छोड़कर चली गई, कितने मांओं ने अपने

बच्चों को न्योछावर कर दिया! जब वह राम मंदिर भव्य बनकर तैयार हुआ तो लगा कि अब राजा राम की भक्ति में कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी, लेकिन बड़ी पीड़ा से कहना पड़ रहा है कि डायन भी ससुराली दो चार घर छोड़ देती है। क्या हमारे अपने राम भक्तों ने रामलला के मंदिर में लालच को नहीं छोड़ा? भ्रष्टाचार कर दिया। पैसा लूट लिया भक्तों का। हां, आरोप यही लग रहा है कि करोड़ों रामभक्त जो रामलला के दर्शन करने जाते हैं और अपनी औकात के हिसाब से 10 रूपया, 5 रूपया, 100 रूपया सोना, चांदी, गहना मंदिर में चढ़ा कर आते हैं उस पैसे में लूट खसोट हुई है।

अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच कर रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हे भगवान राम, हे रामलला तुम्हारा घर भी नहीं छोड़े। वैसे राम नाम भी

गजब की माया है। एक जमाना था जब अयोध्या में पहली बार रामलला के दर्शन होने पर के.के. नायर, जो मजिस्ट्रेट थे, उनके ड्राइवर बाद में विधायक बन गए थे और इस बार जिन पर आरोप लगा है-चंपत राय, जो मंदिर ट्रस्ट के हैं। उनके ड्राइवर हैं जो रईस बन गए हैं। ये आरोप लग रहा है कि 24 कमरे का उनका हॉस्टल है, लिफ्ट वाला मकान है, लखनऊ में करोड़ों की जमीन है। एक दान गिनने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा, जिनकी तनख्वाह अठारह-बीस हजार रुपए है, उनके पास आई फोन निकला है। उनके घर में लाखों रुपया कैश निकला है। करोड़ों की नकदी का हेरफेर हुआ है। अब ये सारे आरोप अभी लगे, लेकिन सवाल फिर वही है कि जिन लोगों पर भगवान राम के भक्तों की श्रद्धा को संभालने की जिम्मेदारी थी, क्या उन लोगों ने श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर लिया? उस मंदिर में जिसको बनवाने के लिए सदियों का इंतजार राम भक्तों ने किया, उसके चढ़ावे पर बुरी नजर डाली। यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि दानपत्र से बैंक जाते-जाते अगर पैसा गायब हो जाता है। एसआईटी जो जांच कर रही है, इसमें गड़बड़झाला मिल रहा है।

अविनाश शुक्ला

सुभाष श्रीवास्तव

रमाशंकर मिश्रा

मनीष यादव

लवकुश मिश्रा

करुणेश पांडेय

अनुकल्प मिश्रा

राम शंकर यादव उर्फ़ टिन्नू यादव

राम मंदिर चंदा चोरी मामले के अभियुक्त

सरकार को जांच बैठाना पड़ रहा है। सीसीटीवी फुटेज गायब होने की बात आ रही है। कर्मचारियों की तनख्वाह, उनके रहन सहन उसमें फर्क दिखाई पड़ रहा है, तो यह सवाल उठेगा कि जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अभी केवल महज चार साल हुए हैं। उसके साथ करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। वह भी राम मंदिर में बैठकर। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसीलिए आज इस बात की बहुत पीड़ा भी है। पीड़ा इसलिए भी क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कितना इंतजार किया। साढ़े पांच सौ साल से अधिक इंतजार किया और इसीलिए जब एक भक्त की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो यह सवाल केवल पैसों का नहीं होता, केवल चढ़ावे का नहीं होता है।

आज इस खबर में दो बातें स्पष्ट होगी-एक अभी आरोप लगे हैं, एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन दूसरा हम योगी आदित्यनाथ सरकार से अपील करेंगे कि अगर यह आरोप प्रमाण में तब्दील हो जाते हैं तो ऐसी नजीर पेश कीजिएगा, जिसका कोई सानी न हो। अगर यह सच निकलते हैं तो इन सब के घर में बुलडोजर चलना चाहिए। इनकी आने वाली पीढ़ी को भगवान मंदिर के आसपास भटकने नहीं देना चाहिए। राम मंदिर के अंदर चोरी कर ली। अभी तक सारे आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं लेकिन अब तक की जितनी खबरें आई हैं क्योंकि अब मामला विपक्ष के आरोप और सत्ता पक्ष के नकारने से ज्यादा हो गया है। सरकार ने खुद एसआईटी बनाई है। तीन आदमी को लगाया है और अगर धुआं है तो पीछे कहीं आग लगी है और उसी आग को समझने की कोशिश करेंगे। यह खबर बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई है? क्योंकि रामलला के चरणों में करोड़ों भक्त अपनी श्रद्धा, विश्वास, मेहनत की कमाई का चढ़ावा समर्पित करते हैं। उसी चढ़ावे को लेकर सवाल है। अब पहले अयोध्या मंदिर कंसेप्ट समझ लीजिए। अयोध्या रामलला मंदिर अगर आप गए हैं तो आप जानते होंगे, वहां पर चौदह जगहों पर दानपत्र लगे हैं। लाखों भक्त रोज आते हैं। लाखों चढ़ावा आता है। कुछ सिक्के के माध्यम से, कुछ नोट के माध्यम से, कुछ सोना, चांदी। श्रद्धालु उसे दानपत्र में डालते हैं। इसके बाद दानपत्र कर्मचारियों की मौजूदगी में खोला जाता है। उसे गिना जाता है और उसके बाद एसबीआई को जमा कर दिया जाता है। लेकिन आरोप यह लग रहा है कि पिछले कई महीनों में यहां गड़बड़ी है। आरोप यह है कि पांच से आठ करोड़ रुपए की कथित गड़बड़ी है। गिनती के दौरान यह कहा जा रहा है कि रकम जो है, जो बैंक पहुंची

वह अलग है। पहले ट्रस्ट को शक हुआ। अंदरूनी जांच की बात सामने आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की। अब बताया जा रहा है कि पचास कर्मचारी ऐसे हैं जो इस भ्रष्टाचार का हिस्सा हो सकते हैं। इनमें से कई कर्मचारियों की तनख्वाह अठारह हजार से पच्चीस हजार रुपए के बीच में है। लेकिन जब आप उनकी संपत्ति और उनके खर्चे को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि उसमें बहुत फर्क है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आई फोन चला रहे हैं। नकद पैसा रखे हैं, लेकिन आरोप यह भी लग रहा है कि विवाद आठ महीने को लेकर है और आठ महीनों में सीसीटीवी फुटेज भी सारी नहीं है और यहीं से जो शक है, जो संदेह है वह धीरे-धीरे यकीन में बदलता है। कुछ तो गड़बड़ है। बताया जा रहा है कि जो गिनती कक्ष था, वहां पर सीसीटीवी नहीं लगाया गया। ट्रस्ट की तरफ से कह दिया गया था कि लड़के अपने हैं। अरे भैया! अपने लड़के घर की दुकान चला रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट चल रहा है। अपने लड़के मतलब? करोड़ों भक्तों की आस्था का सवाल है। पारदर्शिता जितनी अच्छी होगी उतना यकीन बना रहेगा। एक आदमी तन पेट काट के कई बार पैसा जमा कर देता है। चलो जिसके पास है संपन्न है उसको तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गरीब आदमी कई बार सौ रुपया मोड़कर रखे रहता कि पैदल चले जाएंगे। हम भगवान को चढ़ा दे रहे हैं। उसको अगर कोई आदमी लेकर मजा ले रहा है या खर्चा कर रहा है तो तो चिंताजनक बात है।

एसआईटी की शुरुआती जांच में जिन व्यक्तियों का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, उनमें सबसे पहला नाम है रामशंकर यादव का, जो 28 साल पहले मंदिर के जो ट्रस्टी हैं चंपत राय के ऑटो टेंपो को चलाते थे। लेकिन अब ये बड़े आदमी बन गए हैं। इनके पास ऑटो टेंपो से निकलकर मंदिर के चढ़ावे की व्यवस्था की जिम्मेदारी है। मंदिर के वीआईपी पास की जिम्मेदारी है। मंदिर की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कामों की भूमिका है। लेकिन आरोप यह लग रहा है कि इन जनाब के पास चौबीस कमरों का अपना हॉस्टल है। जो मकान बनवाए हैं, लिफ्ट वाला मकान बनवाए हैं। लखनऊ में इनके पास संपत्ति है और करोड़ों की जमीन जायदाद इनके पास है। एक के.के. नायर

साहब थे। मंदिर के शुरुआती दौर में मजिस्ट्रेट साहब अयोध्या के जिनका ड्राइवर विधायक बन गया था और एक चंपत राय जी हैं जिनका ड्राइवर रईस बन गया। करोड़ों का पैसा छाप लिया। ऐसा आरोप लग रहा है अब तक। सच क्या है? वह सामने आएगा जब कोर्ट कचहरी से मामला सामने आएगा।

दूसरा नाम जो निकल कर आया वह है लवकुश मिश्रा का। लव कुश भगवान राम के पुत्र थे। लेकिन इन लवकुश पर आरोप लगा है कि यह दान गिनने वाले वह कर्मचारी थे, जिनकी तनख्वाह अठारह से बीस हजार रुपए थी। लेकिन इन्होंने पैसे में हेरफेर किया है। उनके ऊपर आरोप लगा कि इनके घर से गोबर के ढ़ेर में नकदी मिला है। अयोध्या में भैया चालीस लाख रुपए प्लॉट खरीदे। आई फोन चलाते थे और ये अकेले नहीं। इनके साथ ही कई और हैं जिनपर आरोप है, उनमें अनुकल्प मिश्रा है, अवनीश है, करुण है, मनीष यादव है। कई और कर्मचारी हैं जिनका नाम सामने आया है। बाहर से भी कई लोग आरोप लगवाएं

हैं। धर्मसेना वाले भी आरोप लगवाएं हैं। तहसील दिए हैं चंपत राय जी के खिलाफ, डॉक्टर अनिल मिश्रा के खिलाफ, गोपाल राव खिलाफ, टिन्नू यादव के खिलाफ। आरोप लगाए जा रहे हैं कि 1989 के सोने, चांदी, हीरे, माणिक बारह सौ पचास अष्टधातु शिलाओं के गायब हो गए हैं। वैसे राम मंदिर में जो चढ़ावा है उसकी चोरी को लेकर ट्रस्ट की तरफ से भी बयान आया था। चंपत राय जी कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं है। जांच की जा रही है। सच सामने आ जाएगा। लेकिन चंपत राय जी के लिए भी बहुत सारे सवाल अब उठने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि चंपत राय जी अगर सब कुछ ठीक था तो गिनती वाले कमरे में सीसीटीवी लगाने का विरोध क्यों किया गया? यह क्यों कहा गया कि सब अपने लड़के हैं। जिस लवकुश पर नाम आया उसका नाम भगवान राम के बेटे के नाम पर है। एक आपका ड्राइवर निकला, जिसकी करोड़ों की संपत्ति है। क्या मंदिर में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई? क्या उसके लिए पारदर्शिता जरूरी नहीं है? एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आठ महीने का सीसीटीवी फूटेज जिसके बारे में कथित तौर पर कहा जा रहा है, नहीं मिला। भक्त तो अपनी आस्था चढ़ाता है, पैसे से कोई मतलब नहीं। हम सब तो इसी में खुश थे कि मंदिर बन गया। विपक्ष सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है और विपक्ष क्यों? भाजपा के नेता विनय कटियार ने सवाल उठाया है, देवकीनंदन ठाकुर ने सवाल उठाया है और बहुत सारे साधु संत महात्मा हैं जो अब सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि ट्रस्ट कह रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन फिर दूसरी तरफ करोड़ों रुपए की बरामदगी, गोबर के ढेर से नकदी, कुछ लोग की बढ़ती संपत्ति। ये सारे सवालों ने राम भक्तों के मन में बेचैनी बढ़ाई है।

जब चौकीदार ही चंपत हो जाए तो फिर खजाना कैसे बचेगा? आज भारत में करोड़ों रामभक्त तड़प कर यही सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि यह मामला किसी नेता, अफसर, कारोबारी का नहीं है। यह मामला उस रामलला के चरणों में चढ़े दान का है, जिसे भक्तों ने अपने भगवान को सौंपा था। अब एसआईटी की जांच के बाद जो खबर आ रही है वो परेशान करने वाली है। चंपत राय समेत कई नाम हैं जिन पर सीधे उंगलियां उठ रही हैं। एफआईआर दर्ज होने की बात कही जा रही है। 2 करोड़ रूपये तो बरामदगी की बात हो चुकी है। कई सौ करोड़ का नुकसान सीधे तौर पर कहा जा रहा है। अगर भक्तों के भरोसे के साथ राम मंदिर में दान पेटी के साथ खेला कर दिया गया है तो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो अभी रामलला के मंदिर में क्या कर रहे हैं? आज राम भगवान के लाखों भक्तों के मन में टीस है। जिन हाथों में हमने आंख मूंद कर अपनी श्रद्धा को सौंपा था, वो हाथ साफ थे या चांदी के कौवा उड़ाने में माहिर थे। हां, आज सवाल उठ रहा है वो चांदी का कौवा कहां उड़ गया। जो एक महिला भक्त ने अपनी मन्नत से बनवाकर अपने हाथ से सौंपा था। वो 200 किलो की चांदी कहां गई जो सात समंदर पार बैठे पूरे समाज ने प्रभु श्री राम के नाम पर भेजी थी। उस चेतावनी का क्या हुआ जो छह साल पहले दी गई थी और किसी ने सुनी तक नहीं। दानपात्र की चाबी किसकी जेब में थी? बिना तलाशी कर्मचारी कैसे आते-जाते रहे? और सबसे तीखा सवाल कि जिन लोगों पर यह आरोप है वो आज भी अपनी कुर्सी से चिपके काहे बैठे हैं। क्या योगी जी, मोदी जी को यह दिखाई नहीं पड़ रहा है? और दिख रहा है तो फिर किसको बचाया जा रहा है? करोड़ों राम भक्तों की आस्था को या फिर चंद लोगों की कुर्सियों को।

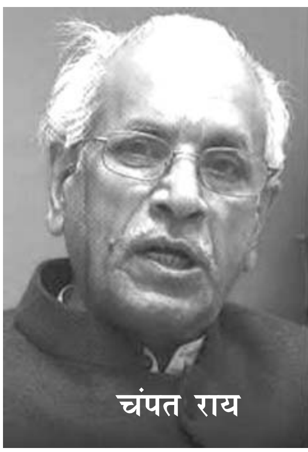
चंपत राय

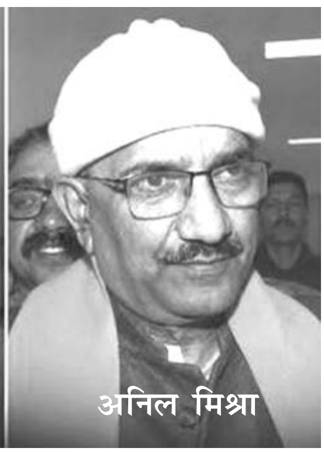
अनिल मिश्रा

विश्व सिंधी सेवा संगम के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष और कास्टलेस ग्रुप के चेयरमैन डॉ. राजू मनवानी ने आरोप लगाया कि पूरे सिंधी समाज ने मिलकर राम मंदिर निर्माण के लिए एक-एक किलो की 200 चांदी की ईंट बनवाई थी, जिन पर समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल की तस्वीर अंकित थी। 26 जनवरी 2021 को 12 देशों से आए 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ये ईंटें खुद चंपत राय को सौंपी गई थी। पर वो कहते हैं कि पांच साल बीत गया। न रसीद मिली, न जानकारी कि वो कहां है चांदी की ईंट। दान के वक्त चांदी की कीमत करीब डेढ़ करोड़ थी, जो आज 6 से 7 करोड़ होगी। यानी अकेले समाज का इतना बड़ा दान और उसका भी कोई हिसाब-किताब नहीं। मनवानी कहते हैं कि पहले सवाल नहीं उठाया क्योंकि भरोसा था कि भाई हमने दिया है, राजा राम के नाम पर दिया है तो राम के काम आया होगा। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि पैसा कौड़ी मार लिया गया है। सैकड़ों करोड़ के हेराफेरी की बात आ रही है तो मन में चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। सवाल आ रहा है कि हम तो राम के नाम पर दिए थे। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी व्यक्ति विशेष ने अपने काम में इस्तेमाल कर लिया। और हैरानी की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे जब एक महिला के चांदी, कौवा और एक पूरे समाज के 200 किलो चांदी तक का हिसाब नहीं तो न जाने ऐसे कितने दान होंगे छोटे मोटे जिनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। ऐसे कितने भक्त होंगे जो यह मानकर लौट गए होंगे कि भगवान के चरणों में उनकी श्रद्धा पहुंच गई। लेकिन कोई उसको अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल कर रहा था।

राममंदिर दान पेटी चोरी का मामले का विरोध देश ही नहीं विदेशों तक व्यापक रूप में हो रहा है। वही राजधानी पटना में हिन्दू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. रमेश शिंदे ने 3 जुलाई को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अयोध्या का श्रीराम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह दुनियाभर के करोड़ों हिन्दुओं के सदियों के बलिदान, दीर्घकालिक संघर्ष और श्रद्धा का प्रतीक है। मंदिर की दानपेटी के अर्पण में चोरी करना एक महापाप है और प्रभु श्रीराम उन्हें उनके कर्मों की सजा अवश्य देंगे। लेकिन सरकार को इस मामले में कौन दोषी है, इसकी शीघ्रता से जांच कर सच्चाई जनता के सामने लानी चाहिए और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग हिन्दू जनजागृति समिति ने की है। हमने इससे पहले भी कई बार यह मांग की है कि किसी भी मंदिर की समिति में केवल भगवान के भक्त ही होने चाहिए। चूँकि भक्त ईश्वर का उपासक होता है, इसलिए वह देव-निधि चुराने का विचार सपने में भी नहीं कर सकता। यदि सच्चे अर्थों में मंदिरों का उद्धार करना है, तो भगवान के ऐसे भक्त ही मंदिर व्यवस्था में होने चाहिए। ऐसे मामलों के कारण सरकार 'मंदिरों

का सरकारीकरण (अधिग्रहण)' करने का प्रयास करती है, जिसका हम हमेशा विरोध करेंगे, समिति ने यह स्पष्ट रुख अपनाया है, जो सरकारी अधिकारी स्वयं भ्रष्ट होते हैं, जो सरकारी अधिकारी शासन तंत्र में गहराई से जड़ जमा चुकी भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा होते हैं, वे सरकारी अधिकारी मंदिर समिति में भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकेंगे? इसलिए धार्मिक स्थलों पर धर्मनिरपेक्ष सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मंदिरों का सरकारीकरण होने के बाद मंदिर के कोष में भ्रष्टाचार बढ़ने के कई उदाहरण देशभर में हैं। इस दृष्टि से भगवान का सच्चा भक्त, जो मंदिर का दायित्व भगवान की सेवा मानकर स्वीकार करेगा, ऐसे भक्तों को ही मंदिरों का दायित्व सौंपा जाना चाहिए।

बहरहाल, राम मंदिर में छह साल पहले खतरे की घंटी बजी थी। आज राम मंदिर ट्रस्ट में जो चोरी चकारी की बात आ रही है, वो अचानक नहीं हुआ है। छह साल पहले ऑडिट करने वाली कंपनी ने साफ-साफ बताया था कि राम मंदिर का इंतजाम ढ़ंग से नहीं चल रहा। कहा गया था कि चंदे और कीमती सामान का रिकॉर्ड सही से नहीं रखा जा रहा। लेनदेन पर दोबारा तिबारा जांच की कोई व्यवस्था नहीं है और अगर यह खामियां रही ऐसी ही तो आगे गड़बड़ी हो सकती है। यानी कई साल पहले रामलला के मंदिर में खतरे की घंटी थी। आवाज आई थी, लेकिन सबने अनसुनी कर दी और सवाल यहीं से शुरू होता है। उस घंटी को अनसुना क्यों किया गया? सीसीटीवी क्यों नहीं लगाया गया? रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा गया? जब किसी जानकार ने उंगली रखकर बता दिया कि सुराख कहां-कहां है तो उन्हें भरा क्यों नहीं गया? क्या किसी को लगा कि भगवान के नाम जो रकम आई उसका हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं? या किसी को इन गड़बड़ियों में फायदा दिख रहा था इसलिए जानबूझकर सुराख को खुला छोड़ दिया गया। जैसे चंपत राय जी ने कहा था क्या जरूरत है अपने तो लड़के हैं। एसआईटी की रिपोर्ट इस शक को गहरा करती है। एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि मंदिर के दानपात्र की चाबी रामशंकर यादव टिन्नू के पास थी। टिन्नू कौन? चंपत राय का ड्राइवर। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सेवादारों को गबन की जानकारी पहले से थी। कौन सेवादार? जिनको चंपत राय जी ने कहा था अपने लड़के हैं। यानी जिस गड़बड़ी की चेतावनी छह साल पहले कागज पर दी गई थी, वो जमीन पर सच होती गई और किसी ने रोका नहीं। अब सीधा सवाल अगर करोड़ों लोगों की आस्था दांव पर थी तो उसकी

रखवाली किसके सिर थी? कुछ सेवादार का ह्रदय पीड़ा से कराह रहा था तो वो भी इनके साथ मिले और बाद में मीडिया को जानकारी दी वरना यह तो नेक्सस रैकेट बना दिया गया था। लेकिन अब सवाल है कि राम मंदिर के चढ़ावे का हिसाब कौन देगा? क्योंकि आज राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो आंकड़े हैं वो परेशान कर देंगे। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी है और इसमें चंपत राय समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें ट्रस्ट के सरस डॉक्टर अनिल मिश्रा, व्यवस्थापक गोपाल राव, व्यवस्था प्रमुख रामशंकर यादव, टिन्नू। एसआईटी ने डेढ़ सौ लोगों से पूछताछ की, जिसमें ट्रस्ट और बैंक के कर्मचारी अधिकारी दोनों थे और कहा जा रहा है कि 25, 30 लोग सीधे-सीधे चोरी की भूमिका में हैं। बरामदगी का आंकड़ा देखिए। पांच आरोपी लवकुश, अवनीश, अनुकलप, करुण, रामशंकर इनकी निशानदेही पर 2 करोड़ रूपये बरामद कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि अभी तो कई सौ करोड़ रुपए ऐसे हैं जो बरामदगी होनी है। कितना सामान कोई सोना का बनवा के कुछ दिया, कोई चांदी का। वो सब गायब है। भक्तों ने दान में गहने दिए थे, वो गायब है और इन सबके बीच चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों की भर्ती पर भी सवाल है। यानी जिन हाथों से करोड़ों राम के भक्तों की श्रद्धा गिनती जा रही थी, उन हाथों के चुने जाने का तरीका भी शक के घेरे में है। और सबसे चिंता की बात जानते हैं मंदिर कर्मचारियों के बिना तलाशी के आवाजाही होती रही। यही ढिलाही इस पूरी चोरी की बड़ी वजह थी।

हालांकि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के चलते चंपत राय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। राय के साथ ही ट्रस्ट के एक प्रमुख और प्रभावशाली सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने भी पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल, चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर के बाद से ही माना जा रहा था कि ये दोनों वरिष्ठ पदाधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इस बीच, खबर है कि अब ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाएगा। हालांकि चंपत राय और अनिल मिश्रा पर सीधे तौर पर कोई वित्तीय आरोप दर्ज नहीं है, लेकिन उनके अधीन काम करने वाली टीम और करीबियों द्वारा इतने बड़े गबन को अंजाम देने और निगरानी में भारी चूक के कारण उन पर भारी दबाव था। अंततः नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दोनों ने ट्रस्ट से अपना त्यागपत्र दे दिया। विवाद बढ़ता देख 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून 2026 को एक 3-सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। एसआईटी ने अयोध्या में 6 दिनों तक डेरा डालकर वित्तीय दस्तावेजों, दानपात्रों के खुलने और नकदी के रख-रखाव से जुड़े रिकॉर्ड्स की गहन जांच की और ट्रस्ट के सदस्यों से पूछताछ की। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर, ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर 25 जून 2026 को अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज की गई। 26 जून 2026 को पुलिस और एसआईटी ने नामजद सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें रमाशंकर यादव (टिन्नू), अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, लवकुश मिश्र, रमा शंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष यादव का नाम है। सवाल यह है कि क्या लोगों ने राम को जो दान दिया था, उसे कुछ लोगों ने अपने बाप की जागीर समझ लिया। क्यों समझ लिया? जांच अपना काम करेगी। सच एक दिन सामने आएगा। लेकिन तब तक यह सवाल सभी राम भक्तों के दिल में कांटे की तरह चुभेगा और इसका जवाब सिर्फ अयोध्या नहीं, आज पूरी दुनिया में बसा हर राम भक्त को देना है। बाकी तो हम यही कहेंगे। हे राम! कैसे किया ये काम?

नितिन नवीन के गाड़ी के आगे नाचे हनुमान

भड़के केजरीवाल, कहा- हिन्दू धर्म पर कलंक हैं ये लोग

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान हुए एक रोड शो ने देश में एक बड़े राजनीतिक और धार्मिक विवाद को जन्म दे दिया है। लखनऊ में रोड शो के दौरान नितिन नबीन के वाहन के आगे भगवान हनुमान के स्वरूप में एक शख्स को भाजपा का झंडा लेकर नाचते हुए देखा गया, जिसका वीडियो वायरल होने के सोशल मीडिया पर लोगों भाजपा की जमकर खबर ली है। साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताते हुए भाजपा से पूरे हिंदू समाज से माफी मांगने की मांग की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दो दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान लखनऊ की सड़कों पर जो नजारा दिखा, उसने अब एक बड़े सियासी घमासान का रूप ले लिया है। दरअसल, नितिन नबीन लखनऊ में एक भव्य रोड शो में शामिल हुए थे। वह एक खुले वाहन पर सवार होकर जनता और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इसी दौरान, उनके वाहन के ठीक आगे भगवान हनुमान का रूप धारण किए एक शख्स हाथ में भाजपा का झंडा लिए ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए आगे बढ़ रहा था। इस दृश्य का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, नेटिजन्स और विपक्षी नेताओं ने इसे आराध्य देव का राजनीतिकरण और मर्यादा का उल्लंघन बताते हुए नाराजगी जाहिर की है। एक यूजर ने प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे किसी अन्य प्रसंग पर कहते हुए दे रहे हैं कि ऐसा कौन बड़ा पदाधिकारी है, जिसके स्वागत में राधा-कृष्ण के भेष में नाचते हुए दिखाते हो, आपकी दुर्गति हो जाएगी।

☞ **क्या शर्म आती है आपको?** :- इस विवाद में सबसे बड़ा राजनीतिक हमला दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (ट्विटर) पर दो तस्वीरें साझा करते हुए भाजपा और नितिन नबीन पर चौतरफा निशाना साधा। केजरीवाल ने अपनी पहली पोस्ट में लिखा- दोनों तस्वीरें हिंदू आस्था के प्रति दो विचारधाराओं की प्रतीक हैं। हमारी विचारधारा हम भगवान राम और हनुमान जी के भक्त हैं और उनमें हमारी श्रद्धा और आस्था है। हम उन्हें पूजते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। इनकी विचारधारा है कि ये लोग हनुमानजी और रामचंद्रजी को भगवान ही नहीं मानते। इनके लिए राम और हनुमान सत्ता और पैसा पाने का जरिया हैं। इन्हें भगवान का अपमान करने में कोई संकोच नहीं होता। इसके तुरंत बाद अपनी दूसरी पोस्ट में केजरीवाल ने और अधिक आक्रामक रुख अपनाते हुए लिखा- जितना नुकसान और अपमान आप लोगों ने हिंदू धर्म का किया है, शायद भारत के 5000 वर्ष के इतिहास में बाहर से आने वाले आतताइयों ने भी नहीं किया, जितना आप लोगों ने हिंदुओं को लूटा है, आज तक किसी ने नहीं लूटा। हिंदू धर्म पर आप लोग कलंक हैं। शर्म आती है आपको? माफी मांगिए पूरे हिंदू समाज से।

☞ **सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस** :- केजरीवाल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया है। एक तरफ जहां आम लोग और विपक्षी समर्थक इसे भाजपा के अहंकार का प्रतीक बता रहे हैं और भगवान के स्वरूप को किसी नेता के आगे नचाने तथा हाथ में दलीय झंडा थमाने की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, भाजपा समर्थकों का तर्क है कि यह कार्यकर्ताओं का अति-उत्साह और एक सांस्कृतिक प्रदर्शन था, जिसे विपक्ष बेवजह तूल दे रहा है। एक यूजर ने लिखा- बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन के स्वागत में, भगवान हनुमान को बीजेपी का झंडा पकड़कर नाचते हुए देखा जा रहा है। एक हिंदू होने के नाते, मुझे यह बात बुरी लगी। लेकिन जो हिंदू मोदी को अपना पिता कहते हैं, वे इसका बचाव कर रहे हैं।

Indore is often celebrated for its vibrant culture, warm hospitality, and carefree spirit. From its famous poha-jalebi breakfasts to lively conversations over tea, the city is known for its positive energy and strong sense of community. Yet behind this cheerful image lies a troubling reality—an increasing number of people are ending their lives, raising concerns among mental health experts and policymakers alike.

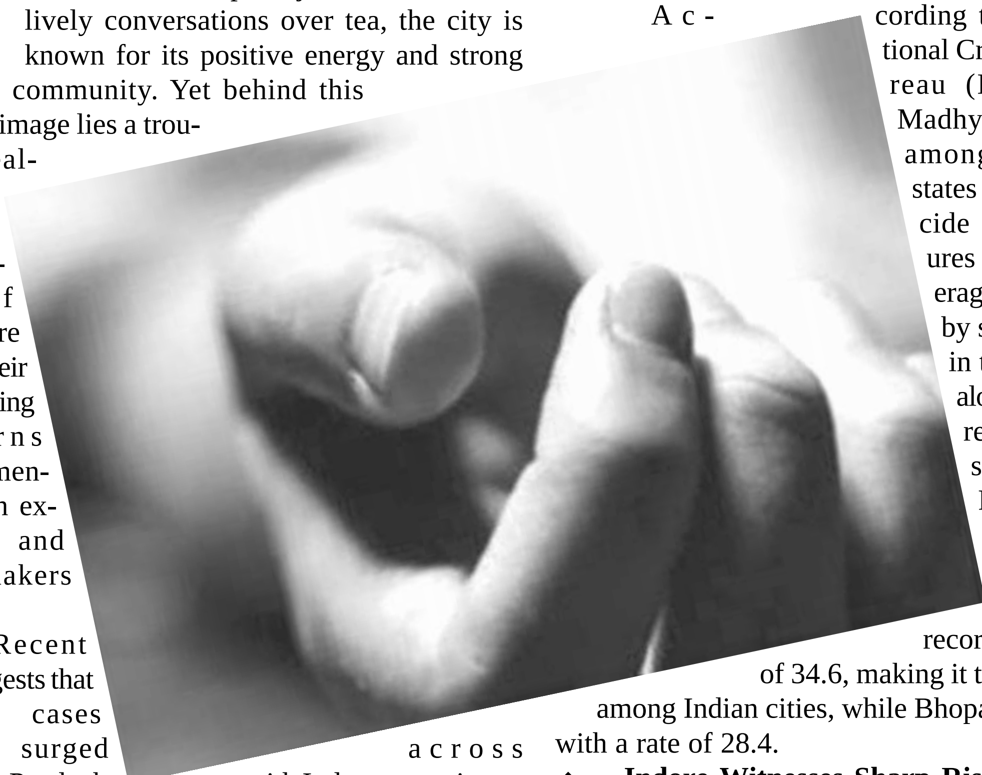

Recent data suggests that suicide cases have surged across Madhya Pradesh, with Indore emerging as one of the most affected cities. While the trend is visible across the state, the situation in Indore has become particularly alarming.

❖ **Madhya Pradesh Among Top Three States in Suicide Cases**

According to the latest National Crime Records Bureau (NCRB) report, Madhya Pradesh ranks among the top three states in India for suicide deaths. The figures reveal that an average of 42 people die by suicide every day in the state. In 2024 alone, 15,491 people reportedly died by suicide in Madhya Pradesh. Even more concerning is the city's suicide rate. Indore recorded a suicide rate of 34.6, making it the fourth-highest among Indian cities, while Bhopal ranked seventh with a rate of 28.4.

❖ **Indore Witnesses Sharp Rise in Cases**

Reports indicate that suicide cases in Indore increased by nearly 30 percent over the past year. More

than 50 suicide cases are being reported every month, with incidents cutting across age groups, professions, and social backgrounds.

Mental health advocates have also pointed out that Madhya Pradesh's proposed State Mental Health Policy, first introduced in 2019, is yet to be implemented.

❖ Key Statistics from Madhya Pradesh

According to NCRB's Accidental Deaths and Suicides Report :-

☞ Housewives: 2,296 suicide deaths
☞ Government employees: 164 suicide deaths
☞ Students: 1,447 suicide deaths
☞ Farmers: 7.9% of total suicide deaths

The report also highlights that Madhya Pradesh accounts for nearly 10% of all student suicides in India. In 2024, 716 male students and 731 female students died by suicide in the state.

❖ Experts Point to Growing Mental Health Challenges

Senior psychiatrist Dr. Satyakant Trivedi of Bhopal says the rise in suicides reflects broader social and psychological changes rather than isolated personal failures.

According to him, people today have more ways to communicate than ever before, yet many feel emotionally disconnected. Constant comparisons on social media, pressure to succeed, unstable relationships, financial uncertainty, and increasing loneliness are taking a significant toll on mental well-being.

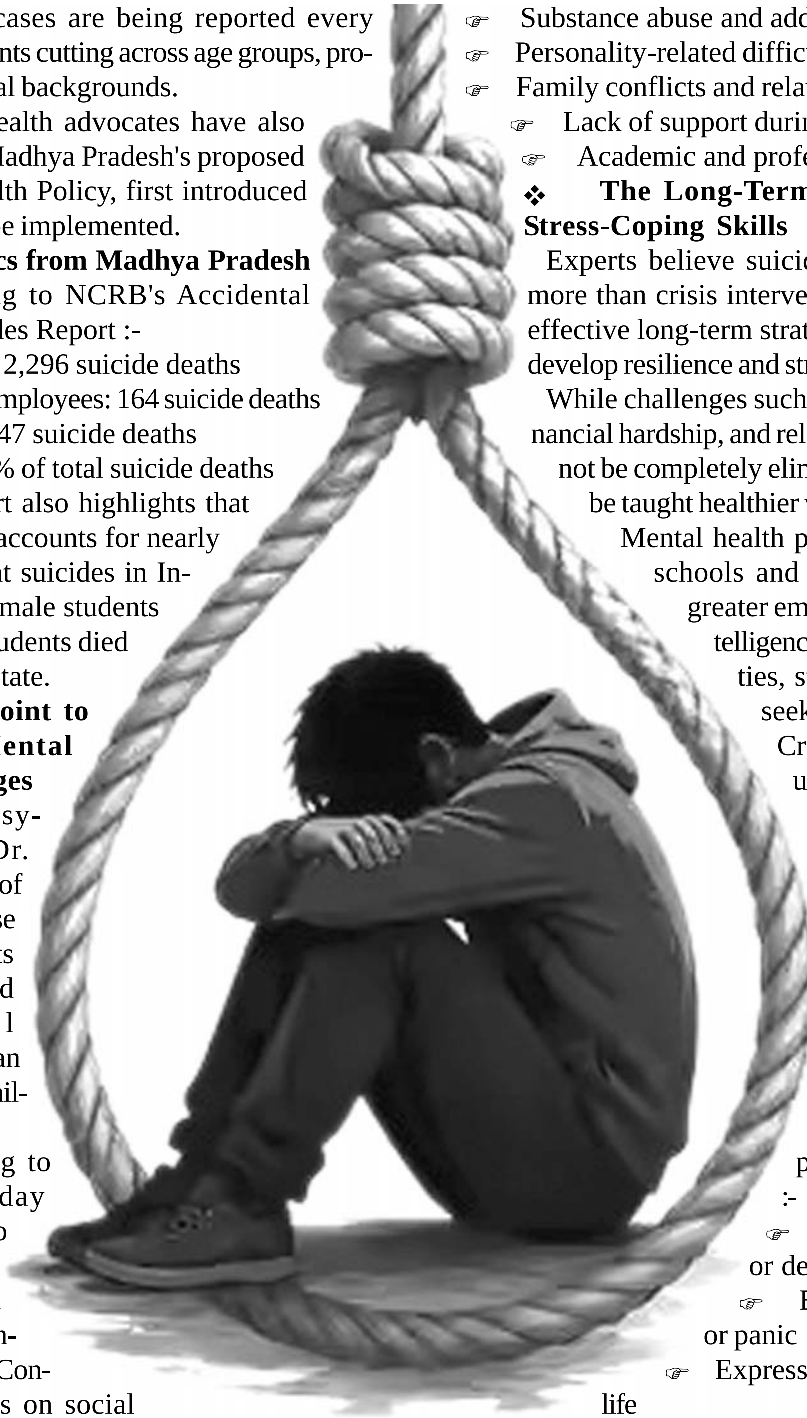

❖ Depression, Anxiety, Addiction Among Major Risk Factors

Mental health experts caution against linking suicide to a single cause. In most cases, multiple factors contribute simultaneously, including :-

☞ Depression and anxiety disorders
☞ Substance abuse and addiction
☞ Personality-related difficulties
☞ Family conflicts and relationship stress
☞ Lack of support during emotional crises
☞ Academic and professional pressure

❖ The Long-Term Solution: Building Stress-Coping Skills

Experts believe suicide prevention requires more than crisis intervention. One of the most effective long-term strategies is helping people develop resilience and stress-management skills.

While challenges such as failure, rejection, financial hardship, and relationship problems cannot be completely eliminated, individuals can be taught healthier ways to cope with them.

Mental health professionals argue that schools and colleges should place greater emphasis on emotional intelligence, problem-solving abilities, stress management, and seeking help when needed.

Creating a culture that values emotional resilience and mental well-being, they say, is essential for reducing suicide rates in the long run.

❖ Warning Signs That Should Not Be Ignored

Experts advise families and friends to stay alert if someone displays the following signs :-

☞ Talking about suicide or death
☞ Excessive anxiety, fear, or panic
☞ Expressing a lack of purpose in life
☞ Increased anger or irritability
☞ Giving away valued personal belongings
☞ Increased use of alcohol or drugs
☞ Social withdrawal and isolation
☞ Spending excessive time alone
☞ Sharing details about personal finances, bank accounts, or important documents unexpectedly

☞ Early recognition and timely support can play a critical role in preventing tragedies.

विकास परियोजनाओं में विस्थापितों की अनदेखी और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ बुंदेलखंड की धरती पर आक्रोश की आग सुलग उठी है। केन-बेतवा लिंक, मझगांव, रूंज, नैगुवा और एनटीपीसी जैसी बड़ी परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर 'जय किसान संगठन' का 'चिता आंदोलन' अब और तेज हो गया है। इस बीच, विस्थापितों के हक की आवाज बुलंद कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर का आमरण अनशन आज 11वें दिन भी जारी है, जिससे शासन-प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। लेकिन प्रशासन जागने को तैयार नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं।

☞ **500 बच्चे, महिलाएं व बुजुर्ग भूखे :** आंदोलनकारियों के अनुसार अनशन के दौरान उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है और अब तक करीब 6 किलो वजन कम हो चुका है। वहीं आंदोलन के समर्थन में बुधवार को भी आंदोलन स्थल पर चूल्हा नहीं जला, जिससे करीब 500 बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भूखे रहे।

☞ **पुनर्वास की मांग तेज हुई :** आंदोलनकारी पिछले चार वर्षों से वे ग्राम सभाओं के आयोजन, पारदर्शी सर्वे, जनसुनवाई, आपत्तियों के निराकरण और उचित पुनर्वास की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि पात्र परिवारों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला, जबकि कई अपात्र लोगों को अधिक राशि दी गई। साथ ही बिचौलियों के खातों में मुआवजा पहुंचने और पुनर्वास प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए हैं।

☞ **परियोजना में कथित भ्रष्टाचार का आरोप :** आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में प्रत्येक विस्थापित परिवार को तीन एकड़ जमीन, कट-ऑफ डेट वर्ष 2026 तक बढ़ाना, परियोजना में कथित भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच तथा केन-बेतवा लिंक परियोजना के लाभ-हानि पर सार्वजनिक चर्चा और कानून के अनुरूप कार्रवाई शामिल है।

☞ **उमंग सिंघार ने लगाए आरोप :** मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने दावा किया कि हाल ही में उन्होंने परियोजना प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जहां की स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि छतरपुर और पन्ना जिले के 14 गांवों के लोग लंबे समय से जमीन अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय प्रशासन बल प्रयोग कर रहा है।

☞ **लाठियां मारकर धरना स्थल से हटाया :** उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि आंदोलन कर रहे

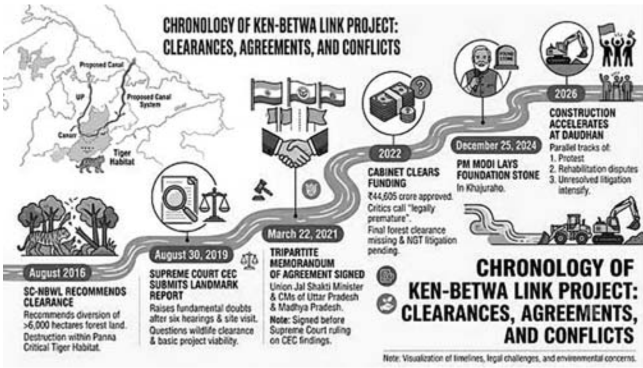

महिलाओं और बुजुर्गों को लाठियां मारकर धरना स्थल से हटाया जा रहा है। उनका कहना है कि परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि कई स्थानों पर बिना ग्रामसभा की वैधानिक अनुमति के किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई। जिन ग्रामसभा प्रस्तावों का हवाला दिया जा रहा है, उनमें वर्तमान सरपंच के हस्ताक्षर तक नहीं हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया की वैधता पर सवाल खड़े होते हैं।

❖ केन बेतवा विस्थापन आंदोलन : अब तक क्या क्या हुआ?

☞ **असंतोष और शिकायतें (4 वर्ष पहले से) :-** प्रभावित ग्रामीण पिछले चार सालों से पारदर्शी भूमि सर्वेक्षण, ग्राम सभाओं के आयोजन, सार्वजनिक सुनवाई और आपत्तियों के सही निपटारे की मांग कर रहे थे। उनका आरोप था कि पात्र परिवारों को कम मुआवजा मिला या छोड़ दिया गया, जबकि अपात्रों और बिचौलियों ने मोटी रकमें ऐंठ लीं।

☞ **प्रशासनिक आश्वासन और विफलता :-** प्रशासन द्वारा बार-बार सूची में सुधार करने और मुआवजा देने के वादे किए गए। प्रशासन ने दावा किया कि 638 छूटे हुए परिवारों को सूची में जोड़ा गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि 'मैनारी' जैसे कई गांवों के नाम अब भी पूरी तरह गायब हैं।

☞ **गिरफ्तारियां और झड़पें (फरवरी 2026) :-** आंदोलन की अगुवाई कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता अमित भटनागर को पुलिस ने शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद बिजावर तहसील में ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। प्रदर्शन हिंसक हुआ, पथराव की घटनाएं हुई और तत्कालीन एसडीएम व अन्य अधिकारी अंदर ही फंस गए, जिसके बाद पुलिस ने कई मामले दर्ज किए।

☞ **पदयात्रा और पीएम को खून से पत्र (मार्च 2026) :-** जेल से रिहा होने के बाद आंदोलन ने फिर जोर पकड़ा। 23 मार्च से पन्ना से छतरपुर के गांवों तक 'न्याय अधिकार पदयात्रा' निकाली गई। 28 मार्च को आंदोलनकारियों ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां

दर्ज कराई।

☞ **चिता आंदोलन (अप्रैल और जुलाई 2026) :-** आंदोलनकारियों ने 'न्याय दो या मार दो' का नारा दिया। श्चिता आंदोलनश के तहत विस्थापित ग्रामीण और विशेषकर आदिवासी महिलाएं प्रतीक के तौर पर बनाई गई चिताओं पर लेट गई। उनका कहना था कि जमीन और जंगल छिन जाने के बाद वे जीते जी मर चुके हैं।

☞ **जल सत्याग्रह और सूली आंदोलन (जुलाई 2026) :-** चिता आंदोलन के बाद ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह शुरू किया, जहां महिलाएं और पुरुष घंटो बराना नदी के ठंडे पानी में खड़े रहे। इसके तुरंत बाद आंदोलन 'सूली आंदोलन' (फांसी सत्याग्रह) में बदल गया, जिसमें ग्रामीणों ने अपने गले में फांसी के फंदे डाले और प्रतीकात्मक फांसी के तख्तों पर खड़े होकर प्रदर्शन किया।

☞ **11 दिनों का आमरण अनशन (ताजा स्थिति) :-** विस्थापितों की मांगों को लेकर अमित भटनागर और पूना नाम की एक आदिवासी महिला अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए। लगातार 11 दिनों तक भूखे रहने के कारण अमित भटनागर का वजन करीब 6 किलो तक घट चुका है और उनकी तबीयत बेहद नाजुक हो गई है। आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन स्थल पर एक दिन खाना तक नहीं पकाया गया।

राजनीतिक मोड़ :- आंदोलन के लगातार खींचने पर मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई विपक्षी नेताओं ने आंदोलन स्थल का दौरा किया और सरकार पर विस्थापित आदिवासियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

☞ **विस्थापितों की मुख्य मांगें :-** भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 का पूरी तरह पालन हो। प्रत्येक विस्थापित परिवार को कम से कम 3 एकड़ कृषि भूमि दी जाए। पुनर्वास के लिए पात्रता की कट-ऑफ तारीख को बढ़ाकर 2026 किया जाए। केन-बेतवा लिंक परियोजना के सामाजिक-आर्थिक लाभों और नुकसानों पर एक खुली सार्वजनिक बहस कराई जाए।

☞ **सीएम यादव को पत्र लिखेंगे सिंघार :-** नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वह पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखेंगे। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाती है तो जमीन अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और परियोजना की प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं की सच्चाई सामने आ जाएगी।

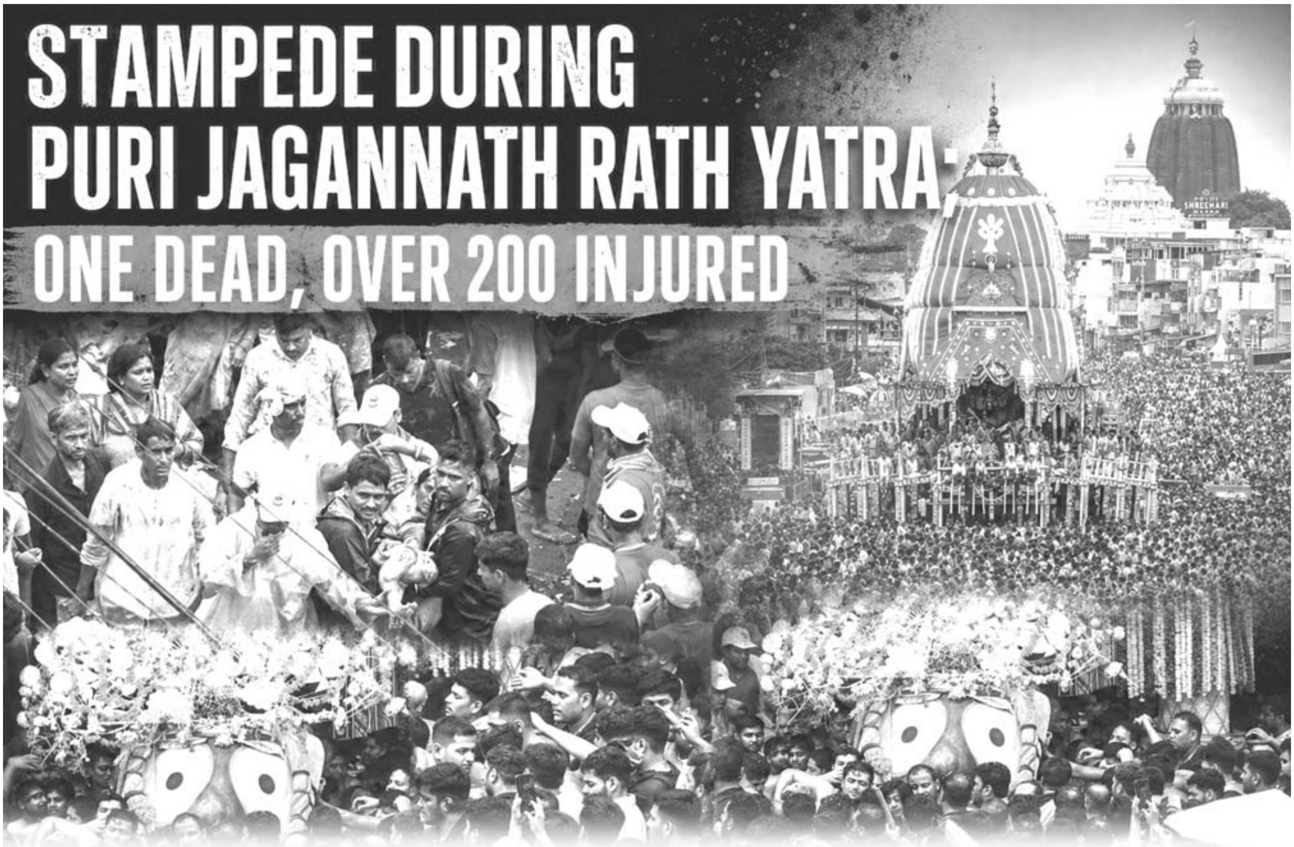

The annual Jagannath Rath Yatra in Odisha's Puri was marred by a stampede on Thursday after massive crowds gathered along the Grand Road (Bada Danda) to witness the procession. According to reports, one devotee lost their life, while more than 200 people were injured in the chaos and rushed to nearby hospitals for treatment.

Stampede Triggered by Massive Crowd

The incident occurred as the chariots of Lord Jagannath, Lord Balabhadra, and Goddess Subhadra were brought out of the Jagannath Temple for the ceremonial procession to the Gundicha Temple. As lakhs of devotees thronged the Grand Road, overcrowding reportedly led to panic and a stampede. Several pilgrims experienced breathing difficulties, and one devotee reportedly collapsed due to suffocation. The person was immediately shifted to the Puri District Headquarters Hospital (DHH), where doctors declared the devotee dead. However, officials had not officially confirmed the fatality at the time of reporting.

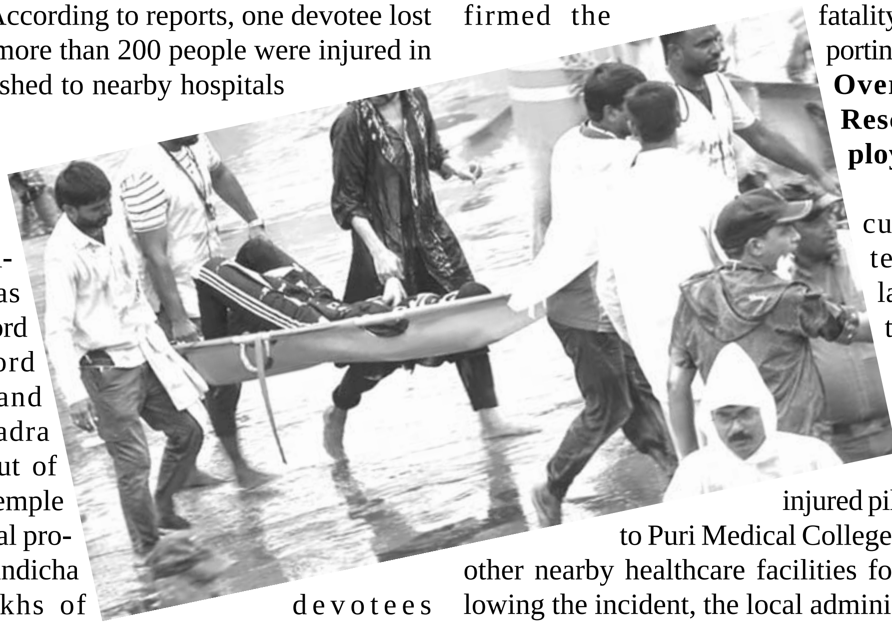

Over 200 Injured, Rescue Teams Deployed

Special Rescue Unit (SRU) teams quickly launched evacuation operations, rescuing injured devotees trapped in the crowd. More than 200 injured pilgrims were taken to Puri Medical College and Hospital and other nearby healthcare facilities for treatment. Following the incident, the local administration strengthened security arrangements and deployed additional police personnel, crowd management teams, and emergency medical units along the Rath Yatra route.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए TMC के तीन बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए के लेन-देन पर रोक लगा दी है। इस कार्रवाई ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है, जिसे भाजपा और टीएमसी के बीच एक नए 'राजनीतिक युद्ध' के रूप में देखा जा रहा है। चुनावों में भाजपा के हाथों सत्ता गंवाने वाली ममता बनर्जी के लिए यह समय सबसे नाजुक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कार्रवाई को देखकर साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक ध्रुवीकरण और तेज होगा। भाजपा इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगा रही है और इसे 'बंगाल की जनता की गाढ़ी कमाई की लूट' करार दे रही है। वहीं दूसरी ओर, विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध और टीएमसी को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की केंद्र सरकार की सोची-समझी रणनीति बता रही है।

☞ **TMC पर क्या होगा असर? :-** इस कार्रवाई का असर तृणमूल कांग्रेस के भविष्य पर काफी गहरा और बहुआयामी पड़ सकता है। दरअसल, ईडी के इस कदम से टीएमसी आर्थिक रूप से पंगु हो सकती है। 440 करोड़ रुपए जैसी विशाल राशि का फ्रीज होना और 18 अन्य खातों का जांच के दायरे में आना TMC की राजनीतिक गतिविधियों को पूरी तरह ठप कर सकता है। दूसरी ओर, ममता बनर्जी ने हमेशा खुद को और अपनी पार्टी को सादगी और शुचिता का प्रतीक बताया है। हवाई जहाज (बिजनेस जेट) और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पार्टी फंड से करोड़ों रुपए के कथित डायवर्जन के आरोपों से ममता बनर्जी की 'हवाई चप्पल और सूती साड़ी' वाली सादगी की छवि पर विरोधी तीखे हमले करेंगे।

☞ **पार्टी में हो सकता है और बिखराव :-** कई विधायक और सांसद टीएमसी का पहले ही साथ छोड़ चुके हैं। पार्टी के मुख्य फंड पर रोक लगने से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट सकता है। फंड की कमी के कारण जमीनी स्तर पर पार्टी कैडर को एकजुट रखना और भाजपा के आक्रामक रुख का सामना करना ममता बनर्जी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन का एक बड़ा चेहरा रही हैं। इस तरह के गंभीर वित्तीय आरोपों के बाद राष्ट्रीय राजनीति में उनकी सौदेबाजी की शक्ति

और साख कमजोर हो सकती है।

☞ **अब तक ED ने क्या-क्या कार्रवाई की? :-** इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने अब तक बेहद आक्रामक और गोपनीय तरीके से जांच को आगे बढ़ाया है। जून में दर्ज हुई एक साइबर धोखाधड़ी की FIR के बाद, मामले की गंभीरता को देखते हुए ED ने मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत जांच अपने हाथ में ली। ED की टीमों ने कोलकाता में 5 प्रमुख ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इसमें 'केयरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज' के परिसर भी शामिल थे।

☞ **18 बैंक खातों को खंगाल रही है ईडी :-** ED ने PMLA की धारा 17(1-ए) के तहत आदेश जारी कर TMC के तीन निजी बैंक खातों में जमा 440.42 करोड़ रुपए के लेन-देन पर तत्काल रोक लगा दी है। जांच में सामने आया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच करीब 160 करोड़ रुपए केयरवेल एविएशन को भेजे गए। इसमें से 112 करोड़ रुपए का इस्तेमाल एक 'एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस जेट' और एक 'अगस्तावेस्टलैंड 109एसपी हेलीकॉप्टर' खरीदने के लिए किया गया, जो कथित तौर पर TMC को किराए पर दिए गए थे। ED के अधिकारी वर्तमान में TMC के कम से कम 18 बैंक खातों को खंगाल रहे हैं। साथ ही केयरवेल ट्रैवल्स, विंडबोर्न एविएशन और अनीता टूर्स जैसी संदिग्ध शेल कंपनियों के ट्रांजैक्शन की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है।

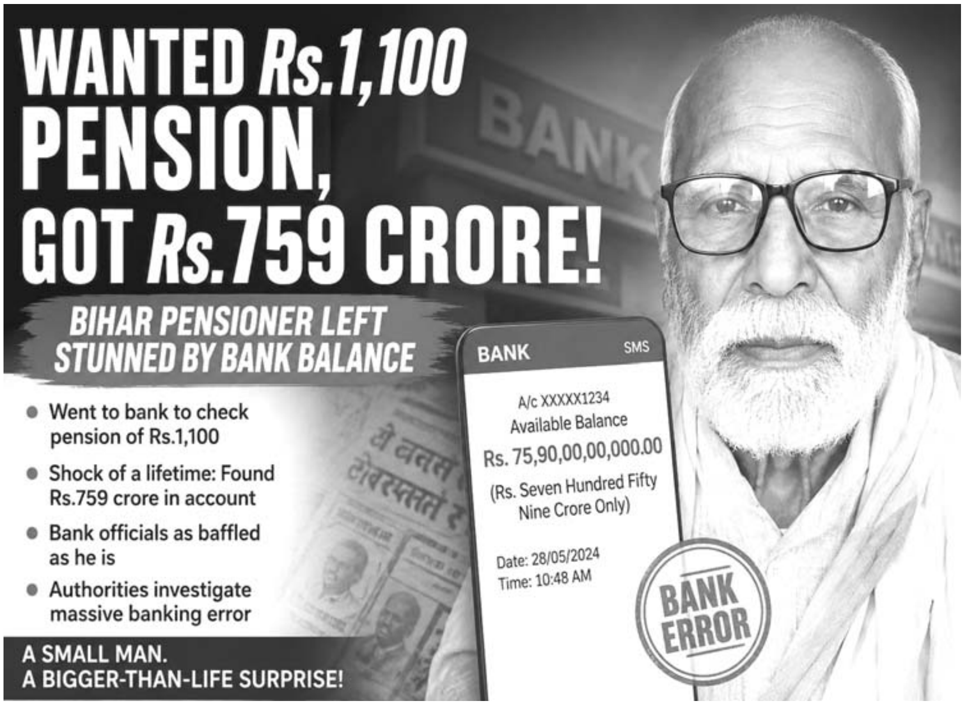

In a bizarre incident from Sarairanjan in Bihar's Samastipur district, an elderly pensioner was left stunned after his bank account displayed a balance of more than Rs.759 crore when he visited a Customer Service Point (CSP) to withdraw his monthly old-age pension of Rs.1,100.

The unusual balance quickly became the talk of the town, drawing crowds of curious locals and prompting an immediate response from bank officials.

❖ Pension Withdrawal Takes an Unexpected Turn

The elderly man had gone to the CSP as part of his regular monthly routine to collect his pension. After biometric verification, the CSP operator checked his account balance and was reportedly shocked by what appeared on the screen. According to the pensioner's family, the operator printed the updated balance in the passbook, revealing an amount exceeding Rs.759 crore.

"We couldn't believe what we were seeing. We had only come to withdraw Rs.1,100. Everyone at the centre was surprised, and we became worried that something had gone wrong," the pensioner's son said.

The family immediately returned home and informed villagers, and within hours the unusual incident spread across the area.

❖ Bank Clarifies: It Was a Technical Error

Bank officials have clarified that the pensioner did not actually receive Rs.759 crore. They said the enormous balance was the result of a technical glitch in the banking system, not a genuine transfer of funds.

According to the branch manager, such errors can occasionally occur during server maintenance, software updates, or data synchronization within the bank's Core Banking System (CBS).

❖ Account Put on Hold

As a precautionary measure, the bank has temporarily blocked all transactions in the account until the issue is fully investigated.

❖ Officials confirmed that :-

☞ The displayed amount does not belong to the account holder.

☞ No actual transfer of ?759 crore was made.

☞ The bank's IT team is working to correct the system error.

☞ The account balance will be restored once verification is complete.

❖ Similar Incidents Reported Earlier

This is not the first time such an incident has surfaced in Bihar. In previous years, account holders in Khagaria and Katihar also found crores of rupees unexpectedly reflected in their bank accounts. Investigations later revealed that those cases were caused by software or server glitches rather than real deposits.

❖ What Should Customers Do?

Banking experts advise customers to avoid withdrawing or spending any unusually large amount that unexpectedly appears in their account. If an incorrect balance is displayed, customers should immediately report it to their bank. Attempting to use money that does not legally belong to them could lead to legal consequences.

While the incident briefly made the pensioner appear to be a billionaire on paper, bank officials have confirmed that it was purely a technical error and that the balance will be corrected after the system review is completed.

● अमित कुमार

क्रांति की जो शुरुआत होती है ना, वो हमेशा एक ब्राह्मण ही करता है! चाहे 322 ईसा पूर्व में चाणक्य हो और चाहे 1857 में मंगल पांडे हो, चाहे वो 1922 में चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे सन् 2026 में भरत भूषण तिवारी हो। अगर आप भरत भूषण तिवारी का सोशल मीडिया एकाउंट देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये जो पुलिस ने उसका फर्जी एनकाउंटर किया है और भरत भूषण तिवारी जो पुलिस से क्रांतिकारी युद्ध शुरू करने की बात करता था। दरअसल इसकी शुरुआत उसने आज से लगभग ढ़ाई साल पहले ही कर ली थी। ढाई साल पहले भरत भूषण तिवारी ने इसकी तैयारी कर ली और भरत भूषण तिवारी को लगता था कि जब वह पुलिस की गोली से

भरत भूषण तिवारी

मारा जाएगा तो समाज में क्रांति आएगी। युवा जागेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। अगर आपको नहीं भरोसा है तो उसके फेसबुक एकाउंट पर 26 दिसंबर 2024 का पोस्ट देखिए। आज से ढाई साल पहले भरत तिवारी ने क्या लिखा–''सत्य और धर्म के रास्तों पर जब तक शांति के सारे रास्ते खत्म न हो जाए तब तक युद्ध को टालते रहना चाहिए। तो अब आगे कुछ दिनों में मैं बिहार के मुख्यमंत्री और भोजपुर प्रशासन को आने वाले युद्ध के लिए आगाह यानी वार्निंग दूंगा। क्योंकि युद्ध का पहला नियम निवेदन करें, विनती करें। अपने समाज के हक में मांगे तो यह सभी नियम मैंने पूरा कर दिया है तो आगे चलकर यह नहीं बोल पाएंगे कि मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं बोला। दूसरा नियम युद्ध न हो, इसके लिए आगे वाले को वार्निंग दे ताकि वह भी संभल सके। तीसरा नियम और जब युद्ध के सिवा कोई

Bharat Tiwari
6d ·

बिहार के CM और बिहार के पुरे सिस्टम को खास करके आरा जिले के पुरे प्रशासन के लिए मेरा इस वीडियो में एक छोटा सा धमाकेदार संदेश और एक चुनौती भी है की अगर जवईनिया गाँव के असहाय और मजबूर लोगो को बसाने के लिए उस गड्ढे वाले स्थान पर 1 से 2 दिनों में मिट्टी नहीं डाला गया (और सभी कार्य अच्छे से नहीं किया गया) यानी की आज और कल में तो उसके बाद बिहार के सिस्टम में बैठा कोई भी साला लुच्चवा और लफंगवा यहां आ गया तो उस साले छपरी का एनकाउंटर कर दिया जाएगा और इस देश में एक नई क्रन्तिकारी युद्ध को छेड़ दिया जाएगा ,

No like no comment

जय हिन्द जय भारत
जय श्री कृष्णा

Bharat Bhushan Tiwari
5 दिन ·

समाज और देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं की बस अब बहुत हुवा अब इस देश में एक नई क्रन्तिकारी युद्ध और एक नई सोच को जन्म देना हिं पड़ेगा ताकी आने वाले भविष्य में हमारा देश पूरी दुनिया में हर छेत्र में सबसे आगे हो और यही मेरा सपना है और यही मेरा संकल्प भी और इसके लिए जो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े वो जरूर दी जाएगी और जो कुछ भी त्याग करना पड़े वो जरूर त्याग दिया जाएगा और अपने देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया जाएगा .

वंदे मातरम भारत माता की जय

तो अब आप सभी को बहुत जल्द बता दिया जाएगा की बिहार में जगदीशपुर के SDM का एनकाउंटर किस दिन किया जाएगा और उसके बाद इस देश में एक नई क्रांति की शुरुवात कर दी जाएगी,

No like no comment ,

जय हिन्द जय भारत
जय श्री कृष्णा

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, भोजपुर (आरा)

(सोशल मीडिया कोषांग)

(दिनांक-16.06.2026)

(जाँच)

शाहपुर थाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है।

कार्रवाई: इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जब शाहपुर थाना की पुलिस टीम संबंधित व्यक्ति के घर पहुँची, तब यह तथ्य सामने आया कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ (विक्षिप्त) है। शाहपुर थाना द्वारा मामले की गहन जाँच की गई है।

मानसिक अस्वस्थता: वीडियो में दिख रहा संबंधित व्यक्ति पूर्णतः मानसिक रूप से अस्वस्थ (विक्षिप्त) है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसके द्वारा इस तरह की कृत्य/बयानबाजी की गई है।

उपचार हेतु कदम: उक्त व्यक्ति की सुरक्षा और सामाजिक शांति को ध्यान में रखते हुए, उसे तत्काल उचित इलाज और देखरेख के लिए मानसिक आरोग्यशाला (Mental Hospital) भेजने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्तमान में, भोजपुर पुलिस और मेडिकल टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को सुरक्षित नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जा रहा है।

हथियार बरामदगी के प्रयास: संबंधित व्यक्ति के पास मौजूद हथियार (आर्म्स) को सुरक्षित रूप से बरामद करने और उसे नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

आम जनता से अपील:

- **प्रशासन आम नागरिकों से यह विनम्र अपील करता है कि कृपया इस भ्रामक वीडियो को आगे शेयर या फॉरवर्ड न करें। अफवाहों पर ध्यान न दें और क्षेत्र में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।**

FOLLOW US @Bhojpur_Police

विकल्प ही ना बचे तो रणभूमि में कूद जाएं। युद्ध कई प्रकार के होते हैं, जिसके अंत में आप बचते हैं या सामने वाला। लेकिन ऐसे युद्ध में मैं किसी को मारूंगा थोड़ी ना। ये लोग कोई आतंकवादी, उग्रवादी, देश विरोधी या कोई ISIS संगठन के लोग थोड़ी ना हैं। अपना पद छोड़ने के बाद ये लोग भी एक आम नागरिक ही कहलाएंगे, तो मेरी मजबूरी है कि मैं एक आम नागरिक को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता। जब तक मेरे जान के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला ना हो। तो इस युद्ध में मैं आगे वाले का नहीं बल्कि अपना बलिदान दूंगा और बलिदान किस प्रकार का होगा आपको जब मैं रणभूमि में कूद जाऊंगा तो बता दूंगा। और ऐसा बलिदान दूंगा कि यह केवल हमारे गांव और हमारे समाज के लिए नहीं अपितु पूरे राज्य और हमारे पूरे देश के लिए सार्थक होगा। उससे एक ऐसी चिंगारी निकलेगी कि हमारे पूरे देश में आग की तरह फैलकर ऐसे लापरवाह राजनेताओं के साम्राज्य को भस्म कर देगी''।

भरत तिवारी ने पहले मांगा, सरकार से निवेदन किया, विनती किया। इसके बाद इसने प्लान बनाया कि मुझे हथियार उठाना पड़ेगा। अब यह इनकी ऐसी सोच थी। भरत भूषण तिवारी साफ कह रहा है, मैं किसी को मारूंगा नहीं। ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो सरकारी लोग हैं, ये लोग भी आम नागरिक हैं और मैं इनको क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। भरत भूषण तिवारी को लगता था कि जब वह पुलिस के गोली से मारा जाएगा तो इस राज्य में एक क्रांति आएगी। क्योंकि राज्य के लोग कराह रहे हैं। ना उनको ढंग का अच्छा भोजन मिल रहा है, ना ही कोई भी काम बिना पैसा दिए, बिना भ्रष्टाचार के हो ही नहीं रहा। इसीलिए भरत भूषण तिवारी को ऐसा लगता था और जब उसको ऐसा लगता था तो आप कह सकते हैं कि वो पागल था। क्योंकि पागल आदमी ही इस तरह का काम कर सकता है। जो आदमी होशोआवास में हो, जो आदमी गंभीरता को समझता हो, बहुत समझदारी से काम लेता है, वो इस तरह का काम नहीं करता। था भरत

भूषण तिवारी पागल! लेकिन वो पागल किसी लड़की के लिए नहीं था। वो पागल किसी का हत्या करने के लिए नहीं था। वो पागल था अपना बलिदान देने के लिए। क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उससे एक ऐसी चिंगारी निकलेगी जो समूचे राजनेताओं के साम्राज्य को भस्म कर देगी। सवाल है भरत भूषण तिवारी क्या करता था? भरत भूषण तिवारी बिलौटी हाई स्कूल का तेजी से होते विकास और कार्यों का फोटो पोस्ट करता था, उसकी तारीफ करता था। पटना, आरा से लेकर बक्सर एन.एस. तक कई जगह पीली लाईट खराब हो चुकी थी, उसे पोस्ट कर जनता के मुद्दे उठाता था। भरत भूषण तिवारी को आप देखेंगे तो बागेश्वर बाबा से मिलने जा रहा है और क्यों मिलने जा रहा है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जब हम उनसे मिल लेंगे तो हिंदू राष्ट्र की मांग

भरत भूषण तिवारी के माता-पिता, भाभी एवं भाई

करेगा। बिलौटी ग्राम में कई स्थान पर सोलर लाइट लगा दिए गए हैं और जो स्थान बचा है वो... मतलब जहां-जहां जरूरत है आवाज उठाने की, वहां वो आवाज उठा रहा है और जहां-जहां जरूरत है कटाक्ष करने की, सवाल पूछने की, वहां-वहां भरत भूषण तिवारी सवाल पूछ रहा है। ये उसके फेसबुक पोस्ट पे आज भी सब कुछ वैसे का वैसे है। इसके बाद भरत भूषण तिवारी जानबूझकर भोजपुर एसडीएम को, डीएम को पोक करने लगा। उन लोगों के बारे में गलत-सलत बात लिखने लग गया। भरत भूषण तिवारी का 3 जुलाई 2025 को यह पोस्ट है, जिसमें लिखा है कि 10 तारीख के बाद बिहार में जगदीशपुर के एसडीएम का एनकाउंटर करके कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। समाज और देश में विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के कारण उसके बाद बिहार के सीएम का भी यही हाल किया जाएगा। जब एक लड़का सोशल मीडिया पर खुलेआम लिख रहा है कि बिहार के सीएम को मार दिया जाएगा, एसडीएम को कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा तो इस लड़के पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ उस समय और उस समय गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या बिहार पुलिस इंतजार कर रही थी इसी दिन का कि किसी दिन यह बहुत बड़ी गलती करेगा और इसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा? क्योंकि यह अलग ही लेवल पर जाके विकास की बात कर रहा था, सवाल पूछ रहा था, लड़ रहा था। क्या इसलिए...? सिर्फ यह एक पोस्ट नहीं है। क्या लिखा है उसने? ''क्योंकि ऐसे लोग हमारे राष्ट्र के लाइसेंसी अपराधी हैं। लाइसेंसी अपराधी और माफिया हैं जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। एक अपराधी को कुत्ते की मौत दी जाएगी तो फिर आगे से हमारे देश में आशा है कि फिर से कोई ऐसा मौत मरना नहीं चाहेगा। हमारे देश से ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहेगा''।

माना भरत भूषण तिवारी का तरीका गलत था। सिर्फ गलत नहीं था, इतना गलत कि हम उसे किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि आखिरकार भरत भूषण तिवारी किस चीज के लिए लड़ रहा था, यह सोचने वाली बात है और उसके सिर्फ एक पोस्ट ऐसे नहीं है जिसमें यह खुलेआम धमकी दे रहा है अलग-अलग नेताओं को और अलग-अलग लोगों को। 26 जून 2025 का पोस्ट है और इसमें भी भरत भूषण तिवारी ने वही बात लिखा है कि ''समाज और देश से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का निकम्मा सीएम और उसके सिस्टम में जो भी ऐसे लोग हैं, खासकर के भोजपुर जिले का जगदीशपुर का एसडीएम और ऐसे लोगों ने समाज में विकास कार्यों को बाधित किया था, अभी भी ये लोग वही कर रहे हैं। ऐसा करके ऐसे लोग समाज और देश को आगे बढ़ने से यानी कि हमारे देश को एक विकसित देश होने से रोक रहे हैं, रोक रहे हैं। इन लोगों ने मानसिक रूप से इस देश को गुलाम बनाकर रखा है''। भरत भूषण तिवारी ने जो किया गलत किया, गलत तरीका था। करना नहीं करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। लेकिन आदमी जब फ्रस्टेड हो जाए, जब सिस्टम इस तरीके से काम करे तो भाई हर आदमी उस मानसिक तनाव को नहीं सह पाता है। भरत भूषण तिवारी नहीं सह पाए। भरत भूषण तिवारी को लगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो देश में

जवानिया गांव में बाढ़ के कटाव से विस्थापितों की आवाज बनते भरत भूषण तिवारी

संजीत कुमार
एसडीएम, जगदीशपुर

Samrat Choudhary
@samrat4bjp

Show translation

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में दिनांक 17.06.2026 को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय चेतना जगेगी। अलग बात है कि राष्ट्रीय चेतना नहीं जगी। लोग अभी भी सवाल नहीं पूछेंगे। भरत भूषण तिवारी की मौत हुई, फर्जी एनकाउंटर हुआ। क्या हुआ सब कुछ चंद दिनों के बाद लोग भूल जाएंगे। भरत भूषण तिवारी के फेसबुक एकाउंट पर किये गये पोस्ट से यह तो पता चलता है कि वह जगदीशपुर एसडीएम और बिहार के सरकारी सिस्टम से परेशान था, फ्रस्टेड था पर पागल नहीं था!

इतना कुछ होने के बावजूद कुछ लोग कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी ब्राह्मण था, सवर्ण था इसलिए सवर्ण इस एनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं। जबकि दूसरे जाति का जब एनकाउंटर होता है, दूसरे जाति के अपराधी का एनकाउंटर होता है तो यही ब्राह्मण, यही सवर्ण खामोश रहते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि अगर मुसलमान का एनकाउंटर हुआ होता तो क्या ये लोग विरोध करते? क्या किसी अन्य जाति के व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ होता तो ये लोग विरोध में होते? ये सारी बातें सरासर गलत है। जब उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, एक भी ब्राह्मण, एक भी सवर्ण ने विरोध नहीं किया क्योंकि विकास दुबे का ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता था। विकास दुबे अपराधी था, उसका एनकाउंटर होना चाहिए था। एक ब्राह्मण नहीं बोलने गया, एक सवर्ण बोलने नहीं गया, एक राजपूत बोलने नहीं गया। लेकिन यहां पर जब आप भरत भूषण तिवारी का इतिहास देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि भरत भूषण तिवारी आखिरकार किस चीज के लिए लड़ रहा था। भरत भूषण तिवारी की मांगें क्या थी और जब पुलिस ने खुद प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यह कह दिया कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से विच्छिप्त आदमी है तो उसका इलाज कराया जाना चाहिए था। उसको पकड़ना चाहिए था। पकड़ के रांची पागलखाने में भेज देना चाहिए था। लेकिन एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। यह विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो फर्जी एनकाउंटर, एक तो एनकाउंटर पर सवाल उठा, दूसरा बिहार पुलिस की खुद की कार्यशैली पर कि जिसे बिहार पुलिस ने खुद मानसिक विच्छिप्त बताया। जो खुद ही इस तरह के फेसबुक पोस्ट करता है कि एसडीएम का एनकाउंटर करके कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। जो मानसिक विच्छिप्त आदमी, जिस पर यह टैग लगा दिया गया उसका एनकाउंटर कर दिया गया। यह कभी हुआ है क्या कि कोई आदमी मानसिक विच्छिप्त हो, पागल हो, उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। और सिर्फ कहा नहीं गया सम्राट चौधरी जी, जो कि इस बिहार के सीएम हैं, उन्होंने खुले मंच से यह ऐलान किया कि हम तो एक विडियो वायरल हो रहा था। हमने देखा कि हमारी पुलिस पर एक आदमी बंदूक

राज
पुलिस अधीक्षक, भोजपुर

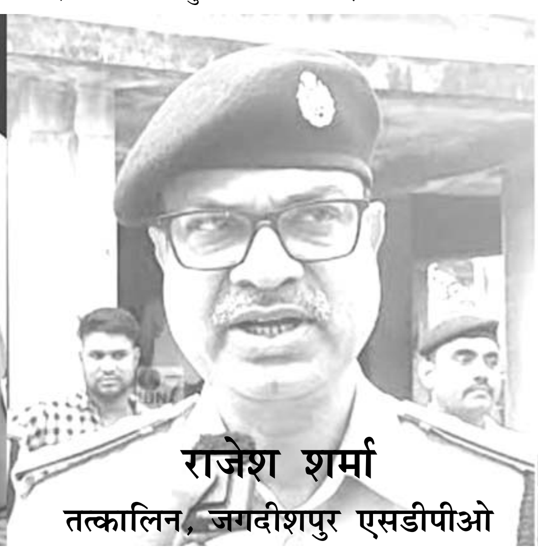

राजेश शर्मा
तत्कालिन, जगदीशपुर एसडीपीओ

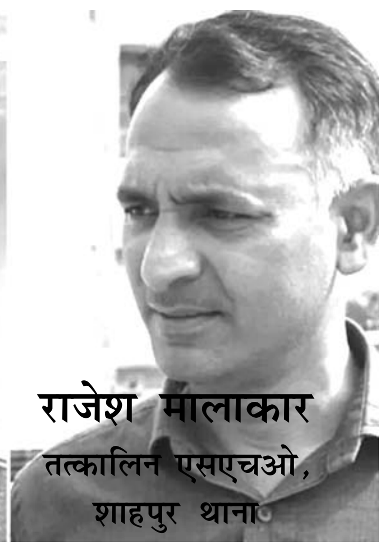

राजेश मालाकार
तत्कालिन एसएचओ, शाहपुर थाना

तान दिया। जब हम पता किए तो पता चला कि वह मानसिक विच्छिप्त है। उसको पकड़ के उसका इलाज कराया जाएगा। यह सम्राट चौधरी जी ने कहा। मतलब सीएम तक को गलत सूचना डीजीपी के द्वारा दी गई। सीएम को बता दिया गया कि मानसिक विच्छित है, उसको पकड़ के उसका इलाज कराया जाएगा और इधर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। जिस एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो गए।

जब तक यह बिहार जातियों में बंटा रहेगा, अपराधियों में जाति खोजता रहेगा तब तक इस बिहार का कुछ नहीं हो सकता। भरत भूषण तिवारी, तिवारी था कि मुसलमान था कि यादव था कि कोईरी-कुर्मी, पासवान था। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ना चाहिए कि भरत भूषण तिवारी किस चीज के लिए लड़ रहा था और जब पुलिस ने उसे मानसिक विच्छिप्त करार दे दिया, इसके बावजूद उसका एनकाउंटर क्यों किया गया? और जब विडियो में साफ दिख रहा है कि भरत भूषण तिवारी ने पिस्तौल दूर फेंक दी। एक सिपाही वाला लपक के उस पिस्तौल को पकड़ता है। इसके बावजूद भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर। इसके बाद भी सवाल न उठे। सवाल इतना उठा कि सम्राट चौधरी जी ने आदेश दे दिया। आदेश जारी कर दिया कि निष्पक्षता से इसकी जांच हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि किसके कहने पर एनकाउंटर हुआ। क्या सिपाही की इतनी ताकत है कि वो किसी लड़के का एनकाउंटर कर दे? क्या पुलिस वालों की या किसी की इतनी ताकत है जब तक से ऊपर से आदेश नहीं आएगा, एनकाउंटर नहीं किया जा सकता। तो ऊपर से आदेश आया। अब आदेश सीएम के पास से आया या बिहार पुलिस के सबसे बड़े पदाधिकारी के पास से आया, ये किसी को नहीं पता। लेकिन आदेश ऊपर से आया, एनकाउंटर नीचे वालों ने किया। सस्पेंड कौन होगा? सबसे नीचे बैठा अधिकारी। सबसे नीचे वाला। ऊपर वाले के इशारे पर काम हो और सस्पेंड हो नीचे वाला। यह है हमारे देश की न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली। जिस पर सवाल उठाना लाजमी है।

भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बिहार भाजपा में भारी विद्रोह हो चुका है। सभी भाजपा नेता सम्राट चौधरी और उनके नेतृत्व समेत गृह मंत्रालय और प्रशासन पर बड़े-बड़े सवाल खड़े कर चुके हैं। जिसमें सबसे बड़ा नाम पदाधिकारी के तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा का है। जिन्होंने तो सीधे तौर पर वीडियो बना कर यह बात कह दी कि रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएगा तो फिर किससे जनता उम्मीद करेगी। उसके बाद बड़ा नाम बक्सर के विधायक आनंद मिश्रा का है। जिन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके सीधे तौर पर लिख दिया कि सरेंडर करने के बाद जो हत्या की गई है, बिल्कुल गलत हुई। उसके बाद राकेश रंजन, जो स्वयं शाहपुर के ही विधायक हैं, जिस क्षेत्र के अंतर्गत भरत तिवारी का निवास स्थान था। उन्होंने तो पिछले दिन मीडिया में बयान देकर यह भी कह दिया था कि हम मुख्यमंत्री जी तक सारी मांगे पहुंचाएंगे, क्योंकि जो हुआ है प्रथम दृष्टया बहुत सही प्रतीत नहीं होता है। विपक्ष के नेताओं को अभी थोड़ी देर छोड़ दीजिए और सबसे बड़ा नाम बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का है। जिन्होंने पुलिस के ऊपर बहुत बड़े-बड़े सवाल खड़े कर दिए। अपनी ही सरकार को घेरे में ले लिया। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व से कोई प्रसन्न नहीं है और इससे भी बड़ी बात यह है कि भाजपा के इन नेताओं का विरोध करने का सीधा अर्थ यह होता है कि शिष्टाचार की पार्टी कही जाने वाली भाजपा, जिसमें यूजीसी जैसे समाज हित के विषय से संबंधित विषय पर भी सभी नेता मौन धारण कर गए थे। उस विषय से भी ज्यादा बड़ा विषय बनाकर भरत तिवारी के विषय पर सभी बोलना शुरू कर चुके हैं। यह साफ दर्शा रहा है कि नेतृत्व किसी को स्वीकार नहीं है वरना भाजपा की परंपरा में इस तरह के सवाल कभी खड़े नहीं किए जाते। विजय कुमार सिन्हा जी ने तो यहां तक स्वीकार कर लिया

Government of Bihar
Home Department

NOTIFICATION

No.- 7146 Patna, dated- 24 June, 2026

Whereas, in exercise of powers conferred under Section 3 (1) of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (No. 60, 1952), the Government of Bihar is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of inquiring into the incident of police action which took place on 17th June, 2026 at Belauthi village under the police station Shahpur in Bhojpur district;

Now, therefore, the Governor of Bihar is pleased to constitute a single member Commission of Inquiry comprising of Hon'ble Mr. Justice Vinod Kumar Sinha, Retired Justice of Patna High Court as its chairman.

2. The Commission will have the following terms of reference :-

I. To inquire into the background of incident, sequence of events and those direct and indirect circumstances, which resulted into occurrence of those incidents.

II. To inquire into the justification of police action at Belauthi village under the police station Shahpur in Bhojpur district on 17.06.2026 and fix the responsibility there for, if necessary.

3. The Governor of Bihar is further pleased to exercise powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the said Act to direct that all the provisions of sub-section (2) (3) (4) and (5) of the said section shall apply to this Commission.

4. The Commission shall submit its report within 06 months from issue of this notification.

By order of the Governor of Bihar

(Kundan Kumar)
Secretary to the Government

प्रेस विज्ञप्ति
सोशल मीडिया कोषांग
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, भोजपुर (आरा)
दिनांक-23.06.2026

(शाहपुर थाना)

शाहपुर थानांतर्गत घटित पुलिस मुठभेड़ से संबंधित घटना के संदर्भ में मृतक की माता द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर शाहपुर थाना कांड संख्या-178/26, दिनांक 22.06.2026 दर्ज किया गया है। उक्त कांड में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जगदीशपुर, तत्कालीन शाहपुर थानाध्यक्ष सहित अन्य सहयोगी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है।

बिहार पुलिस
जन विश्वास संकल्प हमारा

FOLLOW US

कि जो चार पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, यह दर्शाता है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि सरकार मान के चल रही है कि चीजें गलत हुई हैं। विपक्ष के नेताओं का बयान सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती का है। प्रियंका भारती ने तो फेसबुक पर लिखकर के यह तक कह दिया कि अगर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराधियों का एनकाउंटर होगा, हर अपराधी ठोका जाएगा और अपराधियों को बिहार छोड़ देना चाहिए तो अपने अपराधिक इतिहास के बारे में वह क्या सोचते हैं, यह भी उन्हें एक बार आकर क्लीरीफाई कर देना चाहिए। केवल इतना ही नहीं है विपक्ष के तमाम नेताओं ने सवाल खड़े किए हो, चाहे भोजपुर के सांसद हों, सुदामा प्रसाद या फिर अन्य नेताओं ने भी अलग प्रकार के सवाल खड़े किए हैं। सवाल तो सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि सत्ता से विद्रोह लेने वाले हर व्यक्ति को अगर ऐसे ही ठोक दिया जाएगा तो फिर क्या इस देश के लोकतंत्र को समाप्त कर देने का समय आ गया है। तमाम नेताओं ने इन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग की है।

भरत तिवारी हत्याकांड को कई दिन बीत चुके हैं। आज की तारीख में स्थिति यह है कि भारत के दो केंद्रीय मंत्रियों का दो अलग-अलग बयान इस देश में जारी हो चुका है। चिराग पासवान बिलौटी गांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परंतु बिल्कुल उलट जब आप एक तरफ देखेंगे तो वह भरत तिवारी, जिसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं था, उनकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस उसका नाम एनकाउंटर दे देती है। परंतु जिन पुलिसकर्मियों के ऊपर हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज हो चुका है, आज तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एसडीपीओ राजेश शर्मा, जो कि उस दौर में तत्कालीन एसडीपीओ हुआ करते थे, उनको प्रमोट करके मद्यनिषेध विभाग में डीएसपी बनाकर पटना में जगह दे दिया जाता है। अब आप सोचिए कि यह कितना बड़ा न्याय का मजाक है कि जिस व्यक्ति के ऊपर हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया और शायद आजाद भारत के इतिहास का सबसे चर्चित केस दर्ज कर लिया गया हो, वह आज खुले में घूम रहा है और जिसके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं किया गया था उसकी हत्या कर दी गई। आज की तारीख में स्थिति बहुत उलट हो चुकी है। तमाम राजनीतिक महकमों में लोग भरत तिवारी को छोटा करने के लिए उनकी जातियों से आंकना शुरू कर चुके हैं। परंतु उन सबका मुंह बंद करने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण तब साबित हुआ जब चिराग पासवान बिलौटी गांव पहुंचे और यह सोचने वाला विषय है कि भरत तिवारी ने काम कभी किसी तिवारी के लिए नहीं किया था। भरत तिवारी ने काम कभी किसी पांडेय के लिए नहीं किया था। भरत तिवारी ने काम कभी किसी शर्मा के लिए नहीं किया था। भरत तिवारी जवनिया गांव के जिन विस्थापितों के लिए काम कर रहे थे, वह उस तबके के लोग थे, जिसके प्रतिनिधि होने का दावा यही वर्तमान सरकार करती है। वह पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के लोग थे। लेकिन आज की तारीख में दलितों के नेताओं में ज्यादातर नेताओं ने बिहार में दुखी किया है। जब अपने बयान में भरत तिवारी को सिर्फ तिवारी बताया।

द्रौपदी मुर्मू
राष्ट्रपति

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में निगरानी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव कुमार सिंह और निर्भया कांड के भी वही वकील थे और आरोपियों के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ते रहे। निर्भया कांड ने देश को हिलाकर रख दिया था और फांसी की सजा दिलाकर ही ये माने। इस केस को भी वही टेकअप कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत है पुलिसवालों के खिलाफ और कोई भी पुलिसवाला बचेगा नहीं, सबको फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर गहन कवरेज करने वाले सिटी पोस्ट चैनल के प्रमुख एवं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष के पास उपलब्ध एफआईआर कॉपी के माध्यम से जो जानकारी है, उसमें कहा गया है कि जो एफआईआर है उसमें 27 जून का पुलिस अधीक्षक कार्यालय, गोपनीय शाखा, जिला-भोजपुर, आरा का मुहर लगा है। जिसमें बीएनएसएस

की धारा 173 के तहत केस दर्ज किया गया है। यह केस शाहपुर थाने में दर्ज किया गया है। एफआईआर नंबर है- 5124023260178 और तारीख- 22/06/2026 को एफआईआर लिखवाने की दर्ज है। इसमें अभियुक्त बनाया गया है, धाराएं अभी नहीं लगाई गई हैं। अनुसंधान के बाद धाराएं लगाई जाएंगी और एफआईआर के अनुसार इसमें थानेदार और डीएसपी को अभियुक्त बनाया गया है, साथ ही अन्य बाकी जो पुलिसकर्मी सहयोगी पुलिसकर्मी थे उन सबको भी अभियुक्त बनाया गया है। भरत के पिता ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे के हथियार डाल देने के बाद उसे मारा गया है। एफआईआर आशा देवी (भरत की माँ) ने दर्ज करवाई है जिसका एफआईआर नं. -178/26 है। एफआईआर में तमाम जानकारी है और अब ये एफआईआर आरा कोर्ट में भी पहुंच चुका है। भरत के परिजन सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। मंत्री अशोक चौधरी गए थे तो कह रहे थे कि भाई वो सरकारी ड्यूटी पर थे। वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं तो जब तक आरोप सामने नहीं आ जाता है, साबित नहीं होता है तब तक उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता का कहना है कि जिस अपराध, जो संज्ञेय

अपराध, जिस संज्ञेय अपराध में सात साल से ज्यादा के सजा का प्रावधान हो उसमें सीजेआई और राष्ट्रपति को छोड़कर किसी को भी राहत नहीं दी गई है। यानी संज्ञेय अपराध है, सात साल से ज्यादा की सजा है तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो वकील का कहना है कि अगर पुलिस तुरंत गिरफ्तार नहीं करती है आरोपी पुलिसकर्मियों को, तो वो आरा कोर्ट में गिरफ्तारी के लिए वारंट की मांग करते हुए वो केस करेंगे।

अब सुप्रीम कोर्ट के वकील आरा पहुंचने वाले हैं क्योंकि उनका कहना है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अगर अगले दो तीन दिनों में गिरफ्तारी नहीं हुई तो दिल्ली से आरा आएंगे और भरत के परिजनों ने फोन भी की है वकील से और कहा है कि आप ही एक आखिरी उम्मीद हैं। आप आइए और पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करिए। अधिवक्ता सुनील ने जो दावा किया है कि उनके पास पुख्ता सबूत है तो अब ऐसे में तो लग रहा है कि इन पुलिसवालों का बचना बिल्कुल ही मुश्किल है। राष्ट्रपति भवन से भी उनका बहुत अच्छा संबंध है और राष्ट्रपति भवन में उन्होंने ही लिखा था पत्र राष्ट्रपति भवन को और उनके पत्र पर ही राष्ट्रपति भवन ने संज्ञान भी लिया और लगातार राष्ट्रपति भवन से मॉनेटरिंग की जा रही है। अब केवल यह सरकार के हाथ की बात नहीं है और पुलिस के हाथ की बात नहीं है। केवल न्यायिक जांच ही नहीं हो रहा है बल्कि राष्ट्रपति भवन के हस्तक्षेप के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर जो मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी सब इंवॉल्व हो गए हैं इस जांच में। राष्ट्रपति भवन से मुख्य सचिव को निर्देश हो चुका है तो लगातार जो अधिवक्ता हैं वो आरा डीएम के संपर्क में हैं, मुख्य सचिव के संपर्क में हैं। आरा डीएम के साथ मुख्य सचिव विडियो कॉंफ्रेंसिंग भी कर चुके हैं और एसडीएम से पूछताछ भी कर चुके हैं। जगदीशपुर

एसडीएम संजीत कुमार का एफआईआर में नाम नहीं है। लेकिन परिजन तो एसडीएम की भूमिका पर ही सवाल उठा रहे हैं। यह भी सवाल उठा रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ उस समय जगदीशपुर एसडीएम संजीत कुमार वहां क्या कर रहे थे? क्योंकि एसडीएम की तैनाती तो तभी होती है जब लगता है कि कहीं भीड़भाड़ है, बहुत लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या है। यहां तो एक नौजवान को पकड़ना था जो हथियार लहरा रहा था। तो यहां तो एसडीएम संजीत कुमार की आधिकारिक तौर पर तैनाती ही नहीं की गई थी, तो सवाल उठ रहा है कि क्यों थे एसडीएम वहां और उसी एसडीएम संजीत कुमार से भरत की लड़ाई भी चल रही थी। अब जो सूत्र बता रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बता रहे हैं कि अब बहुत जल्द डीएसपी के खिलाफ और एसडीएम के खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है। पहले तो वहां ज्यादा उम्मीद है कि वहां के आरा के डीएम, एसपी, एसडीएम सब बदले जाएंगे और एसडीएम के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। डीएसपी अभी तक जो निलंबित नहीं है, उत्पाद विभाग में उनकी पोस्टिंग हुई है। उनके निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है, तो अब बहुत तेजी से जांच आगे बढ़ रही है। सरकार हर स्तर पर, एक तरफ तो न्यायिक जांच का आदेश सरकार ने दे ही दिया है, वो जारी है। दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। परिजन तो एसडीएम पर आरोप लगा ही रहे थे और साथ-साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो भरत तिवारी का मोबइल था, उसमें बहुत सारे साक्ष्य थे। उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है।

एक तस्वीर पुलिसकर्मियों की भरत के परिजनों ने जारी की है। उसमें एक पुलिस अधिकारी के साथ एक बुलेट प्रूफ जैकेट में एक पुलिसवाला दिख रहा है और उसको देखकर ही भरत की भाभी चिल्ला रही है कि तुम मेरे घर में कैसे आ गए, तो उस पुलिसवाले की क्या भूमिका थी? भरत की भाभी क्यों चिल्ला रही है? उसका कहना है कि जब वो थाने पर गई थी, भरत के पिता को थाने पर बिठाकर इसी पुलिसकर्मी ने रोक कर रखा था। एक तरफ एनकाउंटर हो रहा था बेटे का और पिता को थाने में बिठाकर रखा गया था। उन्होंने कहा भी था कि मुझे बंधक बना लिया गया। जब भरत की भाभी के साथ इस पुलिस वाले ने बत्तमीजी करने की कोशिश की थी। उनके मोबाइल छीनने की कोशिश की थी और जब 18 तारीख को उनके घर पहुंचा, वो तो देखकर भड़क गई। तो बड़ा गंभीर आरोप है। कौन है पुलिसकर्मी और क्यों बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर के भरत के घर गया। अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये कौन पुलिसकर्मी है जिसको देखकर भरत के परिजन काफी डरे सहमे हुए हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी बहुत अहम भूमिका रही है एनकाउंटर में। तो अब जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगा, कई नाम सामने भी आएंगे।

भरत तिवारी के मोबाइल के बारे में कुछ पता चला? क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे साक्ष्य होने की बात कही गई। बिल्कुल मोबाइल के बारे में तो उनके पिता, उनकी भाभी, उनके परिवार वाले सारे सवाल उठा रहे हैं कि भरत का मोबाइल कहां है। क्योंकि उस मोबाइल में उनका कहना है कि एसडीएम के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं घोटाले के और उसी घोटाले के साक्ष्य के कारण ही भरत निशाने पर आए। सवाल तो अब ये भी उठने लगे हैं कि कुछ राजनेताओं के भी इसमें हाथ हो सकते हैं। क्योंकि जब भी जिला स्तर पर या प्रखंड स्तर पर कोई भ्रष्टाचार, कोई सरकारी योजना में भ्रष्टाचार होता है तो उसमें कहीं ना कहीं से नौकरशाहों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हो जाते हैं

अमिताभ कुमार दास

सम्राट चौधरी

मुकेश सहनी

और इस बाढ़ कटाव पीड़ितों के लिए जो राशि दी गई है, जैसे गंगा पर बांध बनाने के लिए, उसके ठेकेदार से रंगदारी मांगने बीजेपी के नेता पहुंच गए थे। ठीक है ना! तो जनप्रतिनिधि जो इस इलाके के हैं, उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है और भरत के परिजनों का कहना है कि अब जांच तो हो ही रही है, अब वो उनके नाम भी आगे करने वाले हैं। उनके नाम के खुलासा करने वाले हैं। जिन नेताओं के एसडीएम से सांठ-गांठ थे, जिन नेताओं का सह था एसडीएम को तो एसडीएम के खिलाफ अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन एसडीएम ठीक से ड्यूटी भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको डर है, भय है, कब टंग जाएंगे, कब पकड़ा जाएंगे।

भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले पर चर्चित आईपीएस अमिताभ कुमार दास का कहना है कि घर के परिजनों ने ऐलान किया है कि वो 9 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठेंगे और उन्होंने पांच मांगों की सूची दी है, तो बाकी मांगे तो खैर ऐसे ही है कि सुरक्षा दीजिए और पारदर्शिता रखिए। मुख्य मांग है कि 8 जुलाई तक जितने भी नामजद अभियुक्त हैं, शाहपुर थाना कांड संख्या 178/26 में जो नामजद अभियुक्त हैं जैसे जगदीशपुर में जगदीशपुर के एसडीपीओ थे राजेश शर्मा, शाहपुर के एसएचओ राजेश मालाकार। इन सब की गिरफ्तारी हो। मुझे नहीं लगता है कि किसी की गिरफ्तारी होगी। अभी तो राजेश शर्मा की मद्य निषेध में तैनाती हो गई है। तो यह भी बात है कि अगर वो बैठ जाएंगी आमरण अनशन पर तब तो फिर वहां नेताओं का जुटान होने लगेगा और फिर बड़ी मतलब एक अजीब स्थिति आ जाएगी, सरकार के लिए और सरकार पर दबाव बढ़ता जाएगा। वही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश शर्मा जो है वो 2007 में मुजफ्फरपुर में थाना प्रभारी था। उस समय में उनके ऊपर आरोप लगा था मनीष वर्मा और उनके दो दोस्त का फर्जी एनकाउंटर करने का। मानवाधिकार यह माना भी स्वीकार भी किया कि इन लोगों ने गलत किया। उन लोगों ने जुर्माना भी भरा। पांच-पांच लाख रुपया भी परिवार को दिया। आप उस समय में इनको अगर सस्पेंड कर देते, उनके ऊपर कार्रवाई कर देते तो आज वो डीएसपी नहीं रहता। उल्टा उनका प्रमोशन हुआ और वो आदमी जगदीशपुर एसडीपीओ बन कर उन्हीं के नेतृत्व में तिवारी जी का हत्या हुआ है और पैसा कमाने में बैठा हुआ है। दारू बेचवाने में बैठा हुआ है, होम डिलेवरी करवाने में थाना बैठा हुआ है। रात को दो बजे गाड़ी कहां खाली करना है। एक गाड़ी

का डेढ़-डेढ़ लाख रुपया, सवा लाख रुपया लेता है। गाड़ी खाली कराने का 800 पेटी का, अगर गाड़ी है तो सवा लाख रुपया। 1200 पेटी का गाड़ी है तो डेढ़ लाख रुपया लेता। गाड़ी खाली कराने का। हमको पता है तो मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पता है? डीजीपी साहब को क्यों नहीं पता है? तिवारी जी का फेक एनकाउंटर हुआ है।

अंत में खबर लिखने तक भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर में नामजद पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है। जांच चल रहे हैं, राष्ट्रपति भवन से दबाव बन रहा है, मुख्य सचिव को तलब किया जा रहा है किन्तु न्याय में देरी बनी हुई है जिससे भरत के परिजन चिंतित हैं। समाज के बीच अन्याय और भ्रष्टाचार करने वालों पर आवाज उठाने की बीड़ा जो भरत भूषण ने उठाया, उसे सबका सलाम है किंतु न्याय के लिए हथियार उठाना गलत था, किन्तु मरता क्या न करता वाली बात है तो भरत ने भी वही किया। उसके साथ छल हुआ, पुलिस ने उसे मार डाला और सभी न्याय की प्रतीक्षा में हैं और न्याय सही और जल्द से जल्द मिले क्योंकि, आने वाले वक्त में किसी भरत तिवारी को न्याय के लिए कट्टे का सहारा ना लेना पड़े। कलम की ताकत से ही न्याय मिलना शुरू हो जाए।

When 18-year-old Nelima Patel sat down to retake the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) medical entrance examination in the western Indian city of Ahmedabad on Sunday, she felt completely drained before the exam had even begun.

The original test in early May was canceled over suspicions that the questions had been leaked. Patel had to prepare all over again, navigating uncertainty, exhaustion and anxiety. "It was mentally exhausting, but I had to keep my wits about me while writing," Patel told DW. "There was just too much preparation that went into it." "Just a few days earlier, another student I knew died by suicide. It was all upsetting," she said.

A generation under unrelenting pressure

Across the country, thousands of students found themselves in a similar position. What was supposed to be the culmination of years of preparation suddenly morphed into just another period of insecurity following the cancellation of the original exam.

This weekend, more than 2 million medical aspirants retook the exam under multi-layered security across thousands of centers, featuring strict surveillance measures like facial authentication, biometric checks and thousands of signal jammers. India offers roughly 130,000 medical undergraduate seats — distributed across more than 800 medical colleges nationwide — for the 2.27 million students who took the NEET medical entrance exam this year. That means fewer than one in 17 candidates can secure a place in a medical college. For many students and their families, the stress is immense.

"It is unfair to put children through such a torturous process," said Rukmini Madhavan, whose son, Mahesh, also took the examination again. "If they don't make the cut-off, the problems are compounded and can have a mental toll," she said.

Growing crisis of student distress

The emotional strain surrounding NEET has once again exposed a larger and more troubling reality of India's growing crisis of student distress. Worryingly, 12 NEET aspirants have reportedly died by suicide in the days since the examination controversy erupted. Some left behind notes detailing the immense strain they were under, while others had expressed anxiety about enduring another round of preparation and testing. Their deaths have sparked fresh questions about an education system in which a handful of examinations often determine access to universities, careers and, many believe, a family's future.

Many of these students come from low-income or rural backgrounds where parents take out massive private loans, sell land, or drain savings to fund years of expensive coaching institute fees.

More than a wake-up call'

India's suicide issue stretches far beyond

NEET. The country recorded 14,488 student suicides in 2024, according to the latest National Crime Records Bureau data released last month. Students accounted for 8.5% of all suicides in the country and represented the fifth-largest occupational category among suicide victims. The figure was 4.3% higher than that of the previous year and continued a decade-long rise that has alarmed mental health experts, educators and policymakers.

"We have created a culture where success is celebrated in very narrow ways, while failure is more often than not stigmatized," neuropsychiatrist Anjali Nagpal told DW. "This is more than a wake-up call, as it can leave young people feeling trapped between expectations and reality."

A highly competitive ecosystem

Students spend months or even years preparing for entrance examinations such as NEET, JEE and a host of government recruitment tests. Teenagers across the country often relocate to places known as coaching hubs, such as Kota in Rajasthan, where they enter a world dominated by rankings, mock tests, cut-offs and relentless competition.

"The pressure to succeed is immense. Failure can mean another year of coaching fees, another year of uncertainty and another year of trying again," Jagdish Kumar, a student in Delhi, told DW. The pressure is compounded by parental expectations, financial sacrifices and the widespread belief that a single examination can alter the course of an entire life.

Educationist Apoorvanand Jha pointed out that the crisis surrounding national examinations has foundational flaws that stem from an unsafe structural obsession. "Forcing a massive country into highly centralized, single-point national examinations does not elevate standards," he told DW.

"Instead, it creates highly vulnerable single points of failure that jeopardize the future of millions of young students, delaying university calendars and academic sessions entirely," Jha underlined.

Top court expresses concern

India's Supreme Court has increasingly expressed concern over what it described as a worsening pattern of student distress. In a series of observations, the top court identified a "disturbing pattern" of student suicides across educational institutions and cautioned against treating them as isolated incidents.

A court-mandated national task force headed by a former Supreme Court judge identified several factors driving the crisis, including extreme academic competition, caste-based discrimination, financial stress, weak grievance redressal systems and inadequate access to mental health support.

From exam halls to politics

The student deaths have now become a rallying point for the Cockroach Janta Party (CJP), a youth movement that emerged from an online satire campaign but quickly evolved into one of India's most talked-about political phenomena.

The CJP continues to hold a sit-in protest in the capital New Delhi. It has capitalized on the NEET controversy, arguing that repeated examination irregularities and administrative failures are eroding trust in a system that millions of students depend on for social mobility. CJP chief Abhijeet Dipke has urged Prime Minister Narendra Modi's government to provide a compensation of 10,000,000 rupees (• 92,418) to the families of the students who allegedly died by suicide amid examination-related controversies.

"Some of these families had taken out loans to educate their children. One can only imagine what these families are going through," said Dipke, whose party is demanding the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. The movement began as a response to a senior government member comparing some unemployed young people to "cockroaches." Its online campaign soon struck a chord with a generation grappling with high joblessness, exam scandals and growing economic insecurity.

Drawing public attention to the problem

The NEET controversy also crystallized wider anxieties about a future increasingly shaped by a handful of make-or-break tests. For Kumar, who is preparing for next year's examination, the issue is less about politics and more about the emotional toll of an unforgiving educational system. "It is the survival of the fittest and that is what the system is geared to," he said.

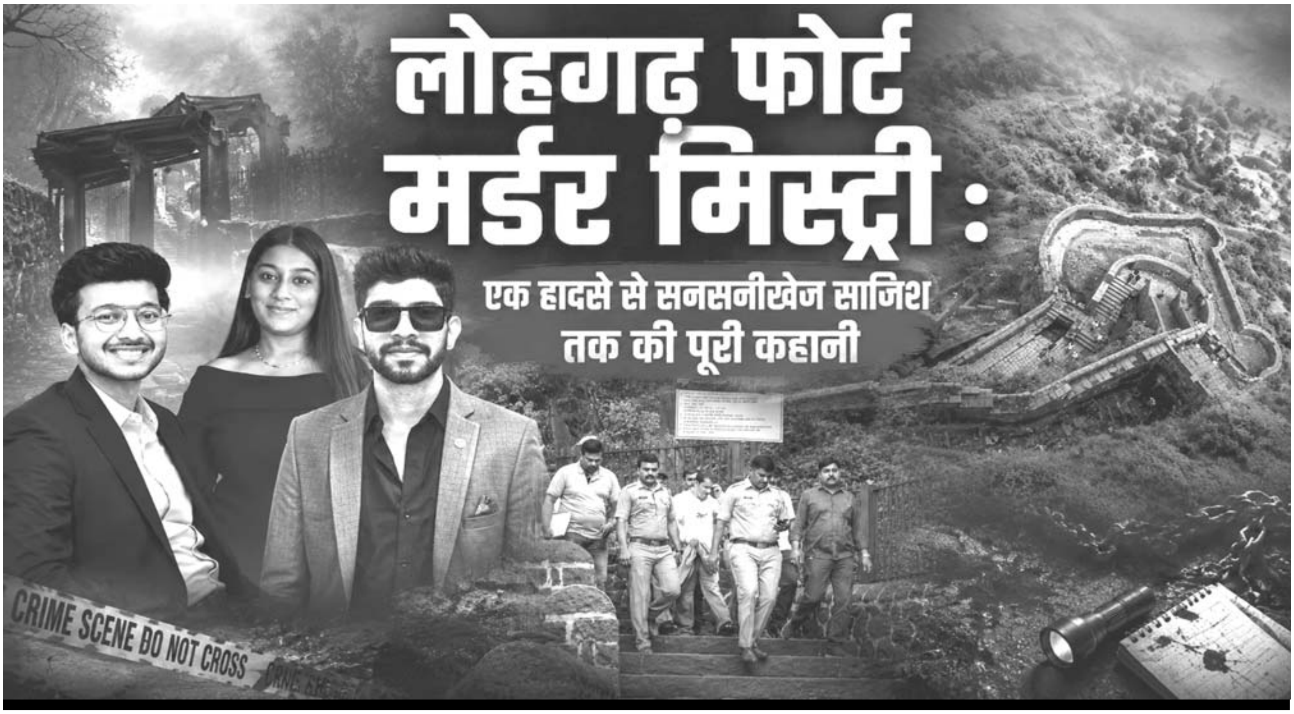

पुणे के व्यवसायी केतन अग्रवाल (26) की मौत का मामला अब एक दुर्घटना से बदलकर पूरी तरह से एक सुनियोजित और खौफनाक कत्ल की साजिश में तब्दील हो चुका है। शुरुआत में इसे लोहगढ़ किले की 400 फीट गहरी खाई में हुआ एक सामान्य ट्रेकिंग हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच और परिवार के खुलासों ने इस मामले को हिलाकर रख दिया है। इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस की पूरी और क्रमानुसार कहानी इस प्रकार है :-

☞ **भव्य सगाई और पनपता शक :-** फरवरी 2026 में केतन अग्रवाल और सिया गोयल (20) की सगाई एक परिवारिक और भव्य समारोह में हुई थी। नवंबर में दोनों की शादी उदयपुर या जयपुर के एक शानदार पैलेस में होने वाली थी, जिसकी तैयारियां जोर-शोर से चल रही थींख्रयहाँ तक कि मेहमानों के लिए चार्टर्ड प्लेन (प्राइवेट जेट) और 17 करोड़ तक के खर्च की तैयारी थी। लेकिन सगाई के बाद से ही केतन को सिया के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। केतन ने अपने परिवार वालों से जिक्र किया था कि सिया का फोन अक्सर व्यस्त रहता है और वह बातचीत के दौरान बार-बार चेतन चौधरी (22) नाम के शख्स का जिक्र करती है। केतन को उसके बैकग्राउंड पर भी शक होने लगा था।

☞ **मर्डर की प्लानिंग और खौफनाक साजिश :-** पुलिस जांच में सामने आया है कि यह कत्ल अचानक नहीं, बल्कि गहरी प्लानिंग का नतीजा था :-

☞ **लोकेशन की रेकी :-** सिया और चेतन ने मिलकर कत्ल को अंजाम देने के लिए कई जगहों का सर्वे किया था। उन्होंने लोनावाला का टाइगर पॉइंट, विसुपर फोर्ट और लोहगढ़ किले की रेकी (त्मबवद. दपेंदबम) की थी, ताकि ऐसी जगह चुनी जा सके जहाँ मौत को आसानी से हादसा साबित किया जा सके।

मंगेतर ही निकली कातिल

- लोहागढ़ किला हत्याकांड में मंगेतर सिया ही निकली केतन की कातिल।
- प्रेमी चेतन के साथ मिलकर 350 फीट गहरी खाई में दिया था धक्का।
- केतन से शादी नहीं करना चाहती थी सिया इसलिए रची खौफनाक साजिश।

☞ **इंटरनेट पर सर्च और फिल्में :-** आरोपियों ने मर्डर के तरीके ढूंढने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया, जहर देने के तरीकों पर गौर किया और कई सस्पेंस-क्राइम फिल्में भी देखी थीं।

☞ **बाली ट्रिप का दबाव :-** जून की शुरुआत में केतन और सिया को बाली (ठंसप) ट्रिप पर जाना था। आरोपियों को डर था कि अगर ट्रिप के दौरान या बाद में सच सामने आ गया, तो वे पकड़े जाएंगे। इसी जल्दबाजी में उन्होंने हत्या की योजना को तेज कर दिया।

❖ **पहले असफल प्रयास और 18 जून की वह खौफनाक घटना :-**

☞ **14 जून की पहली कोशिश :-** पुलिस के मुताबिक, 14 जून को भी सिया ने केतन को लोहगढ़ किले पर एक बार गिराने की कोशिश की थी। तब केतन झाड़ियों को पकड़कर किसी तरह बच गया था। उस समय सिया ने तुरंत ष्सांप-सांपष चिल्लाकर बात को घुमा दिया था और ड्रामेबाजी करते हुए कहा था कि वह तो केतन को बचाने की कोशिश कर रही थी।

☞ **18 जून (जन्मदिन का बहाना और कत्ल) :-** सिया ने अपने जन्मदिन (18 जून) को मनाने का बहाना बनाकर केतन को फिर से लोहगढ़ फोर्ट चलने के लिए राजी किया। तय योजना के मुताबिक चेतन चौधरी भी पहले से वहां मौजूद था। जैसे ही सिया ने एक तयशुदा इशारा (बैठकर सिग्नल देना) किया, चेतन पीछे से आया और केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया।

☞ **सबूत मिटाने और गुमराह करने की कोशिश :-** घटना के बाद सिया बिल्कुल भी विचलित नहीं दिखी, जिससे परिवार का शक गहरा गया। आरोपियों ने अपने फोनों से चौट हिस्ट्री और रीसायकल बिन तक डिलीट कर दिए थे, जिन्हें पुलिस ने रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा है। पूछताछ के दौरान दोनों पहले पुलिस को गुमराह करते रहे और एक-दूसरे पर इल्जाम

मढ़ते रहे, लेकिन बाद में कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

☞ **पुलिस कार्रवाई और परिवार का दर्द :-** पुणे ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने क्राइम सीन रीक्रिएशन (अपराध स्थल का पुनः निर्माण) भी किया है। केतन के परिवार और स्थानीय लोगों ने न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाला। वहीं, आरोपी सिया के पिता ने भी मीडिया के सामने आकर कहा कि अगर उनकी बेटी दोषी है, तो उसे भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

सोनम, सिया के बाद अब समिता!

इश्क में अंधी महिला अधिकारी ने 4 लाख की सुपारी देकर कराया पति का कत्ल

बिहार के कटिहार से जो दास्तान निकलकर सामने आई है, उसने न सिर्फ कानून के रखवालों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि रिश्तों पर से इंसान का भरोसा उठा दिया है। यह कहानी हैख्र अंधे इश्क, सरकारी रुतबे, बेवफाई और एक बेगुनाह पति के बेरहम कत्ल की है। सुपौल में तैनात श्एमवीआईश् (मोटर यान निरीक्षक) समिता कुमारी के पास रुतबा था, पैसा था और समाज में इज्जत थी। लेकिन इस रसूखदार मैडम के दिल के भीतर एक ऐसा राज दफन था, जिसकी भनक उसके पति देव कुमार गुंजन को भी नहीं थी। समिता का दिल नालंदा में बिजली विभाग के ग्रेड-वन टेक्नीशियन अजीत कुमार पर आ चुका था। मगर इस इश्क के बीच सबसे बड़ा रोड़ा था समिता का पति देव, जो कि जमुई में पदस्थापित था और अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करता था। समिता और अजीत के लिए देव कुमार अब एक ऐसा कांटा बन चुका था, जिसे रास्ते से हटाए बिना उनके मिलन की अधूरी हसरत पूरी नहीं हो सकती थी।

☞ **पति की जान की कीमत 4 लाख :-** इश्क में अंधी हो चुकी मेमसाब और उसके टेक्नीशियन प्रेमी ने मिलकर एक ऐसी खौफनाक साजिश रची, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। समिता ने पति की जान की कीमत लगाईख्रपूरे 4 लाख रुपए। इस खूनी खेल को अंजाम देने के लिए हायर किया गया जहानाबाद के घोसी थाने का एक पुराना हिस्ट्रीशीटर और शार्प शूटर राजू कुमार, जो हाल ही में मर्डर के केस में जमानत पर बाहर आया था।

☞ **11 जून की वह काली रात :-** देव कुमार गुंजन अपनी पत्नी समिता से मिलने के लिए बड़ी उम्मीदों और प्यार के साथ श्जनसाधारण एक्सप्रेसश् में सवार हुआ। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन देव कुमार इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी मौत भी उसी ट्रेन में सफर कर रही है। जैसे ही ट्रेन मानसी रेल थाना क्षेत्र के बदलाघाट के पास पहुंची, बोगी में अचानक चीख-पुकार मच गई। शूटर राजू कुमार ने तमंचा निकाला और चलती ट्रेन में देव कुमार को गोलियों से भून डाला। खून से लथपथ देव कुमार ने वहीं दम तोड़ दिया।

☞ **मगरमच्छ के आंसू और :-** वारदात के बाद शातिर समिता ने फौरन एक लाचार और बेकसूर विधवा का मुखौटा पहन लिया। वह पुलिस के सामने छाती पीट-पीटकर रोने लगी। शुरुआत में पुलिस को भी लगा कि यह चलती ट्रेन में हुई डकैती की वारदात है। लेकिन कहते हैं न कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वह कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। कटिहार के रेल एसपी हरिशंकर कुमार और उनकी टीम को मैडम की ओवर-एक्टिंग और बयानों में झोल नजर आ गया।

☞ **मोबाइल ने उगल दिया श्काली रातोंश् का सच! :-** मामले की तह तक जाने के लिए रेल पुलिस ने स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम का गठन किया। जब पुलिस ने समिता कुमारी का मोबाइल जब्त कर उसके श्कॉल डिटेल रिकॉर्डश् (ब्क्त) और मोबाइल लोकेशन को खंगाला, तो पुलिस की आंखें फटी रह गईं। घटना के वक्त और उससे पहले, समिता के फोन से उसके प्रेमी अजीत और शूटर राजू के बीच लगातार रहस्यमयी और कोड-वर्ड्स में बातचीत हो रही थी। जब तकनीकी साक्ष्य सामने रखे गए, तो श्कातिल हसीनाश् का सारा नकाब उतर गया।

☞ **सलाखों के पीछे पहुंचे गुनाहगार :-** पुलिस की सख्त पूछताछ के आगे प्रेमी अजीत कुमार टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि उसी ने समिता के साथ मिलकर इस खूनी ताने-बाने को बुना था। पुलिस ने शूटर राजू को भी दबोच लिया है। समिता कुमारी अब कानून के शिकंजे में है। जिस मांग के सिंदूर को उसने 4 लाख रुपए की सुपारी देकर मिटा दिया, अब उसी गुनाह की सजा काटने वह सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है।

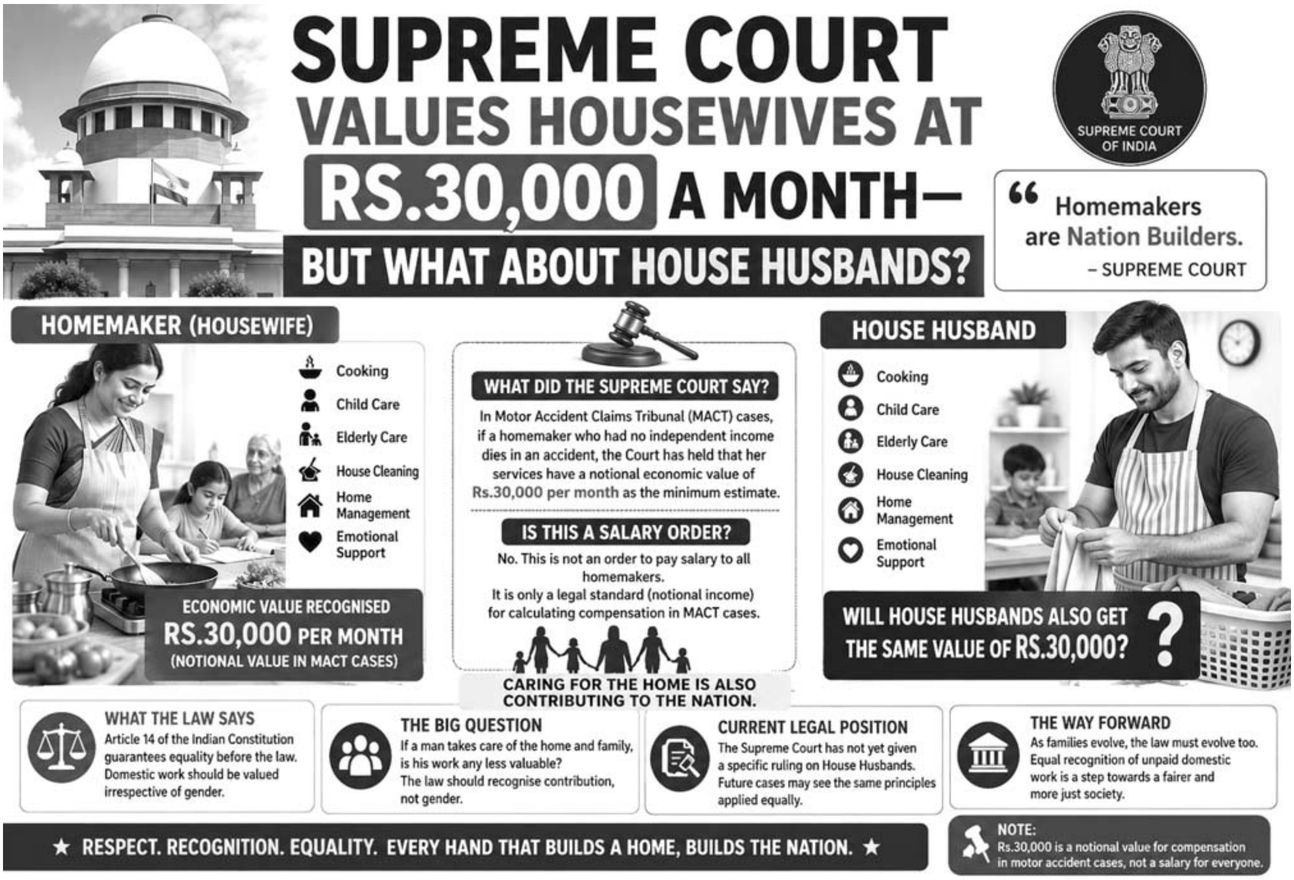

In a landmark judgment that could reshape how domestic work is viewed in India, the Supreme Court on June 11, 2026, recognized homemakers as "nation builders" and fixed a minimum notional income of Rs.30,000 per month for calculating compensation in motor accident claim cases.

The ruling is being hailed as a major step toward acknowledging the economic value of unpaid household work performed by millions of women across the country. However, it has also sparked an important debate: if domestic labor deserves compensation and recognition, should the same principle apply equally to house husbands?

A Historic Shift in How Domestic Work Is Valued

A bench comprising Justice Sanjay Karol and Justice N. Kotiswar Singh delivered the verdict while hearing a motor accident compensation case dating back to 2001. The Court observed that it is ironic to treat homemakers as financially dependent on earning family members when, in reality, entire households often function because of their efforts.

For decades, courts frequently assessed the value of a homemaker's contribution using the benchmark of unskilled labor, resulting in compensation calculations based on notional incomes as low as Rs.3,000 per month. The latest judgment significantly changes that approach by assigning a minimum notional income of Rs.30,000 per month. The Court also directed that this amount should increase by 10% every three years to account for inflation and changing economic realities.

Additional Benefits for Working Women

The ruling goes a step further by clarifying that if a woman is employed and also manages household responsibilities, the value of her domestic contribution should be considered separately and added to her actual earnings while determining compensation.

This acknowledges the "double burden" many women carry by balancing professional careers and unpaid domestic work.

What Is 'Loss of Domestic Care'?

The Supreme Court clarified that compensation should not be limited to lost income alone. The concept of "Loss of Domestic Care" should include :-

☞ Household management and daily operations.
☞ Childcare and maternal care.
☞ Emotional and practical support provided to family members.

☞ Caregiving responsibilities that contribute to family well-being.

The judgment recognizes that these contributions have significant economic value even though they do not generate a direct salary.

Why the Verdict Matters

Experts believe the decision could provide much-needed financial security to families, especially in rural and middle-class households, where homemakers play a central role in maintaining family life. The Court noted that women contribute substantially to India's economy through unpaid labor and spend significantly more time on household responsibilities than men. By assigning monetary value to domestic work, the judgment challenges long-standing assumptions that household labor lacks economic worth.

The Unanswered Question : What About House Husbands?

Interestingly, the Supreme Court acknowledged that the term "homemaker" is often associated with women, but men can also perform the same role—either by choice or due to family circumstances. However, the judgment largely focuses on the traditional model of a female homemaker. This has raised an important question in legal and social circles: Should compensation for domestic work be gender-neutral?

Changing Family Dynamics in India

Modern Indian households are evolving. Increasingly, some men are taking on full-time domestic responsibilities while their spouses pursue careers. These house husbands manage childcare, cooking, budgeting, cleaning, and overall household operations—performing many of the same duties traditionally associated with homemakers. Critics argue that if a house husband were to die in an accident, treating him merely as a "dependent" rather than recognizing his domestic contribution would contradict the spirit of the Supreme Court's ruling.

Toward True Equality

The Supreme Court has previously observed in judgments delivered in 2021 and 2024 that a wife's domestic work should be valued on par with a husband's office work. Many legal experts now believe the next logical step is extending that principle equally to all homemakers, regardless of gender.

If domestic labor has economic value, they argue, that value should not depend on whether the work is performed by a woman or a man.

Challenges Ahead

While the verdict has been widely welcomed, its implementation will require consistency across Motor Accident Claims Tribunals (MACTs) nationwide. Legal experts suggest that detailed guidelines and specialized training may be necessary to ensure uniform application of the new compensation framework.

There are also calls for broader reforms, including social security benefits, pension schemes, and welfare measures for homemakers and house husbands alike.

A Progressive Beginning

The Supreme Court's decision marks a significant step toward recognizing the dignity and economic importance of domestic labor. It acknowledges that nation-building happens not only in offices and factories but also within homes. Yet the conversation is far from over. As Indian society continues to evolve, the debate may increasingly shift from recognizing homemakers to recognizing all caregivers equally—regardless of gender.

True equality, many argue, will be achieved when the value of running a household is measured by the work itself, not by who performs it.

समुद्र तल से करीब 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि प्रकृति का अद्भुत चमत्कार भी है। यहां हर वर्ष प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिम शिवलिंग (बाबा बर्फानी) श्रद्धालुओं के लिए भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है, लेकिन इस साल प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग लगभग पूरी तरह पिघल गया है। 57 दिन चलने वाली यात्रा 5वें दिन ही शिवलिंग पूरी तरह से पिघल गया। इस साल यात्रा के लिए करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कठिनाई भरे रास्तों से बाबा एक झलक पाने के लिए कठिन रास्तों से पहुंचे भक्तों को निराशा हाथ लगी। शिवलिंग का इतनी जल्दी पिघलना कहीं प्रकृति का मानवों को एक बड़ी चेतावनी तो नहीं।

आखिर यह हिमलिंग बनता कैसे है? क्या यह केवल चमत्कार है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया भी काम करती है? इस बार यह सवाल इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों में हिमलिंग का आकार तेजी से छोटा हो गया है। बीएसएफ द्वारा 23 मई को जारी तस्वीरों में हिमलिंग की ऊंचाई लगभग 7 फुट दिखाई गई थी। 29 जून को पहली पूजा के समय भी इसकी ऊंचाई 5 फुट से अधिक थी, लेकिन 3 जुलाई तक इसका आकार घटकर करीब 4 फुट रह गया। 2006 में शिवलिंग तीर्थ यात्रा शुरू होने से पहले ही पवित्र गुफा से विलुप्त हो गया था। 2004 में तीर्थ यात्रा लगभग एक महीने तक चली और भगवान 15 दिनों के के अंदर बाबा बर्फानी पिघल गए थे। 2013 में 22 दिनों और 2016 में 13 दिनों में अंदर शिवलिंग पिघल गया था। बता दें कि शिवलिंग किसी कलाकार द्वारा बनाई गई बर्फ की कलकृति नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। अमरनाथ का हिमलिंग पूरी तरह प्राकृतिक भू-वैज्ञानिक प्रक्रिया से बनता है।गुफा की छत के ऊपर मौजूद चूना पत्थर और जिप्सम की चट्टानों के बीच से ग्लेशियरों का पिघला पानी धीरे-धीरे रिसता है। जब यह पानी बूंद-बूंद करके गुफा के फर्श पर गिरता है

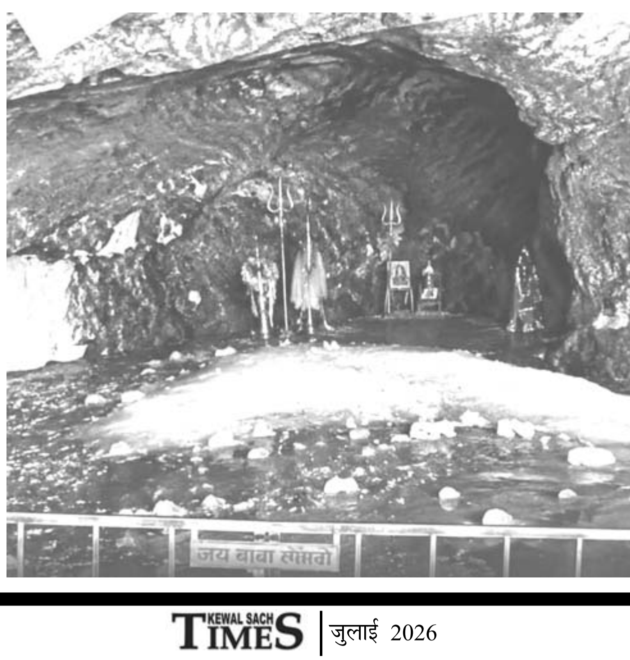

तो गुफा के भीतर मौजूद शून्य से नीचे तापमान में जमने लगता है। समय के साथ ये जमी हुई परतें ऊपर की ओर बढ़ती जाती हैं और एक बर्फ का स्तंभ तैयार हो जाता है। यही प्राकृतिक बर्फ का स्तंभ श्रद्धालुओं के लिए बाबा बर्फानी या हिम शिवलिंग है।

अमरनाथ मंदिर किसी इंसान द्वारा निर्मित मंदिर नहीं है। प्राकृतिक चूना पत्थर और जिप्सम की गुफा वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढंकी रहती है। गुफा के भीतर मुख्य हिमलिंग के अलावा दो छोटे हिम स्तंभ भी बनते हैं जिन्हें श्रद्धालु माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। अमरनाथ गुफा दुनिया के रहस्यमयी स्थानों में शामिल है, जहां प्रकृति, विज्ञान और आध्यात्मिक आस्था एक साथ दिखाई देते हैं। विज्ञान हिमलिंग बनने की प्रक्रिया को समझाता है, जबकि श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। यही कारण है कि अमरनाथ केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि विश्वास, प्रकृति और रहस्य का अद्भुत संगम बन चुका है। हिन्दू पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक माता पार्वती ने भगवान शिव से उनकी अमरता का रहस्य

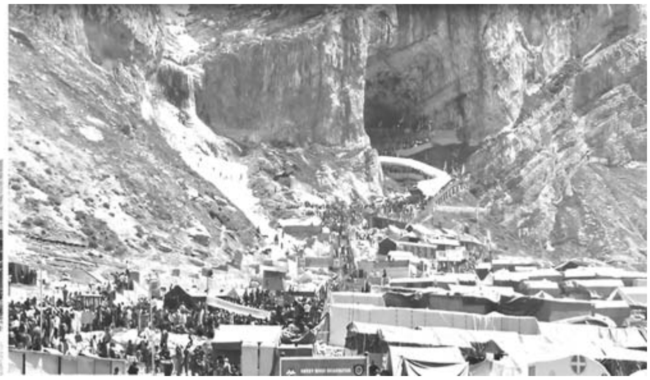

पूछा था। भगवान शिव उन्हें यह रहस्य बताने के लिए ऐसी जगह की तलाश में निकले जहां कोई जीवित प्राणी मौजूद न हो। इसी कारण उन्होंने अमरनाथ गुफा को चुना। रास्ते में उन्होंने पहलगाम में नंदी को छोड़ा। चंदनवाड़ी में अपने मस्तक से चंद्रमा को अलग किया। शेषनाग झील के पास सर्पो को त्याग दिया। महागुणस पर्वत पर भगवान गणेश को छोड़ा। पंचतरणी में पंचमहाभूतों का त्याग किया। इसके बाद अमरनाथ गुफा में समाधि लगाकर उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। कथा सुनते समय माता पार्वती कुछ देर के लिए सो गई, लेकिन गुफा में मौजूद कबूतरों के एक जोड़े ने पूरी कथा सुन ली और अमर हो गए। आज भी कई श्रद्धालु गुफा में कबूतरों का जोड़ा दिखाई देने का दावा करते हैं।

क्या बाबा के 'अदृश्य' होने के पीछे केवल मौसम जिम्मेदार है या फिर हिमालय का बदलता पर्यावरण, बढ़ती गर्मी और इंसानी गतिविधियां भी इस पवित्र स्थल के प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर रही हैं? वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक यह केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन की ओर इशारा है। इसके लिए केवल भीड़ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और बदलते मौसम की भूमिका इससे कहीं अधिक बड़ी मानी जा रही है।

कब-कब अंतर्ध्यान हुए हैं बाबा बर्फानी :-

☞ 2013 में 16 फुट से बाबा बर्फानी 7 फुट के ही रह गए।

☞ 2012 में शिवलिंग का आकार 22 फुट से घटकर 12 फुट हो गया था।

☞ 2011 में 16 फुट के बाबा बर्फानी ने दर्शन दिए थे, जो महज 5 दिनों में 4 फुट तक पिघल गए थे।

☞ 2010 में 12 फुट के शिवलिंग का आकार पिघलकर पहले 6 फुट हुआ और बाद में 3 फुट हो गया था।

शिवलिंग काआकार हर साल मौसम, बर्फबारी, तापमान और गुफा के भीतर मौजूद प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि तापमान सामान्य से अधिक रहता है या बर्फबारी कम होती है तो हिमलिंग जल्दी पिघलने लगता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में जम्मू-कश्मीर और पूरे हिमालयी क्षेत्र में मौसम का पैटर्न तेजी से बदला है। सर्दियों में अपेक्षाकृत कम बर्फबारी और गर्मियों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है। गुफा के भीतर बर्फ लंबे समय तक टिक नहीं पा रही है। पहले जहां हिमलिंग अगस्त तक सुरक्षित रहता था, लेकिन अब यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद बर्फ पिघलने से आकार तेजी से घटता है।

हर बार रक्षा बंधन से पहले ही भक्तों के सांसों की गर्मी से तेजी से पिघलता अमरनाथ यात्रा का प्रतीक हिमलिंग एक बार फिर विवाद का मुद्दा बन चुका है। अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने इसके पिघलने की प्रक्रिया से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर कश्मीर के पर्यावरणविद इसे मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि क्षमता से अधिक श्रद्धालुओं को यात्रा में शामिल होने की अनुमति देने से ऐसा हुआ है। पिछले कई सालों से जिस तेजी से हिमलिंग पिघल रहा है उसे रोकने की खातिर किए जाने वाले उपाय नाकाफी साबित हो रहे

है।

दरअसल गुफा में क्षमता से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने से हिमलिंग को नुक्सान पहुंच रहा है, क्योंकि लाखों भक्तों की गर्म सांसों को हिमलिंग सहन नहीं कर पा रहा है। श्राइन बोर्ड के अधिकारी अप्रत्यक्ष तौर पर भक्तों की सांसों की थ्यूरी को मानते हैं, पर प्रत्यक्ष तौर पर वे इसे कुदरती प्रक्रिया करार देते थे। श्राइन बोर्ड के अधिकारी कहते थे कि ग्लोबल वार्मिंग भी इसे प्रभावित कर रही है। वे इससे इंकार करते थे कि गुफा में क्षमता से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वर्ष 1996 के अमरनाथ हादसे के बाद नितिन सेनगुप्ता कमेटी को आधार बना सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिदिन 15 हजार से अधिक को यात्रा में शिरकत करने से रोक दिया था पर इस बार तो 8 दिनों में 2 लाख अर्थात प्रतिदिन 25 हजार के हिसाब से श्रद्धालु गुफा में पहुंच चुके हैं। इस पर पर्यावरणविद खफा हैं। वे कहते हैं कि यात्रियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि न सिर्फ हिमलिंग को पिघलाने में अहम भूमिका निभा रही है, यात्रा मार्ग के पहाड़ों के पर्यावरण को भी जबरदस्त क्षति पहुंचा रही है पर श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं की संख्या को कम करने को राजी नहीं दिखता है। लेकिन वह हिमलिंग के संरक्षण की योजनाओं पर अमल करने का इच्छुक जरूर दिखता है। श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं की संख्या को कम करने की बजाय यात्रा को सारा साल चलाने के पक्ष में भी समर्थन जुटाने में जुटा हुआ है जिसके लिए अब सड़क तैयार की जा चुकी है तो गंडोला भी लगाने की तैयारी हो रही है। यात्रा शुरू होने के बाद भक्तों के अलावा गुफा के आसपास बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं। भारी भीड़ की वजह से अमरनाथ गुफा के आसपास का तापमान और बहुत बढ़ गया है, हालांकि श्राइन बोर्ड ने दावा किया था कि पिछले दो-तीन साल में उन्होंने कुछ ऐसे उपाय किए हैं, जिससे गुफा का तापमान न बढ़े। जब 28 जून को बाबा बर्फानी ने पहली बार दर्शन दिए थे तब शिवलिंग का आकार करीब 10 से 12 फुट का था और धीरे- धीरे वह अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। ये पहला मौका नहीं है जब बाबा बर्फानी पहली बार अपने भक्तों से रुठे हों, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है।

जब भारत का कोई युवा वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाता है, तो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली और बेहद प्रेरणादायक कहानी सामने आई है आईआईटी कानपुर के ग्रेजुएट सिद्धार्थ सक्सेना की। सिद्धार्थ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने महज 26 साल की उम्र में एक ही दिन में 8 मिलियन डॉलर यानी करीब 77 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जहां इस उम्र में ज्यादातर युवा अपने करियर को सेट करने में संघर्ष कर रहे होते हैं, वहीं सिद्धार्थ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है।

☞ **कौन हैं सिद्धार्थ सक्सेना? :-** राजस्थान के अलवर के रहने वाले सिद्धार्थ सक्सेना एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहने वाले सिद्धार्थ ने साल 2019 में देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान प्प्ज कानपुर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक पूरा किया। सिद्धार्थ ने बताया कि भारत में आईआईटी से कंप्यूटर साइंस करना कितना कठिन है। मशहूर कंटेंट क्रिएटर विराज अला को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया, ष्आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस कोर्स में एडमिशन पाना, अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने से भी 20 गुना ज्यादा मुश्किल है।

☞ **कैसे एक ही दिन में कमाए 77 करोड़ रूपये? :-** आईआईटी से पास आउट होने के बाद, सिद्धार्थ अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को चले गए। साल 2022 में, जब दुनिया में जनरेटिव एआइ की लहर शुरू हो रही थी, तब सिद्धार्थ ने अपने आईआईटी कानपुर के बैचमेट्स प्रग्युष राय और सिर्शेदु सरकार के साथ मिलकर 'मर्लिन' नाम का एक एआई-पावर्ड क्रोम एक्सटेंशन लॉन्च किया। यह टूल देखते ही देखते कामकाजी लोगों और प्रोफेशनल्स के बीच सुपरहिट हो गया। आज इनके इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन 50 मिलियन डॉलर (लगभग 415 करोड़ रूपये से अधिक) हो चुकी है। जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा कितना कमाया, तो सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मैं आपको इससे भी बेहतर कुछ बताता हूं। मैंने एक ही दिन में 8 मिलियन डॉलर (करीब 77 करोड़ रुपए) कमाए।' जब उनसे पूछा गया कि क्या वह रातोंरात करोड़पति बन गए, तो उन्होंने कहा, ष्हां, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए।ष

☞ **भारतीयों की सोच और अमेरिका के माहौल में है बड़ा फर्क :-** सिद्धार्थ ने इस मुकाम तक पहुंचने के अपने अनुभव को साझा करते हुए एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में सीमित संसाधनों की वजह से ज्यादातर लोग 'कमी की मानसिकता' के साथ बड़े होते हैं, जहां रिस्क लेने से डर लगता है। सिद्धार्थ सक्सेना के अनुसार, हम एक ऐसी मानसिकता से आते हैं जहां पैसे की कमी होती है, लेकिन एक बड़ी कंपनी खड़ी करने के लिए आपको 'प्रचुरता की मानसिकता' की जरूरत होती है। अमेरिका में लोग रिस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि वे उस काम से प्यार करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें सर्वाइव करने के लिए वो काम करना ही है। सिद्धार्थ ने यह भी स्वीकार किया कि जब वह 16 साल के थे, तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कभी जीवन में इस मुकाम पर पहुंचेंगे। भारत के एक छोटे से शहर से निकलकर अमेरिका में मल्टी- मिलियन डॉलर कंपनी खड़ी करने वाले सिद्धार्थ आज देश के लाखों युवाओं के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं।

✯ **फिशिंग और ओटीपी फ्रॉड से बचने के तरीके क्या हैं?**

फिशिंग और ओटीपी फ्रॉड डिजिटल धोखाधड़ी के सामान्य रूप हैं, जहां ठग संवेदनशील जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। इनसे बचाव के लिए सतर्कता और सरल आदतें अपनाएं।

❖ **फिशिंग से बचाव :-**

☞ अनजान ईमेल, एसएमएस या लिंक पर क्लिक न करें; सीधे आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

☞ संदेशों में व्याकरण त्रुटियां या जल्दबाजी की मांग हो तो संदेह करें और भेजने वाले की पुष्टि करें।

☞ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट रखें।

❖ **ओटीपी फ्रॉड से बचाव :-**

☞ कभी भी ओटीपी, पासवर्ड या बैंक विवरण फोन, मैसेज या ईमेल पर न शेयर करें, भले ही कॉलर बैंक का दावा करे।

☞ संदिग्ध नंबर ब्लॉक करें और आधिकारिक नंबर पर खुद संपर्क करें।

☞ बैंक स्टेटमेंट नियमित जांचें और अनधिकृत लेनदेन पर तुरंत रिपोर्ट करें।

☞ शिकायत cybercrime.gov.in पर दर्ज करें या 1930 पर कॉल करें। जागरूकता से 90% फ्रॉड रोके जा सकते हैं।

निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि नए जमाने का नए प्रकार का साइबर अपराध जो अब एक विकराल रूप ले चुका है क्योंकि अब साइबर अपराध एक राष्ट्रीय समस्या नहीं है बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, इससे आज के समय में सभी प्रभावित हैं चाहे वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस हो, जज हो, व्यवसायी हो, छात्र हो, महिलाएं हों सभी लोग इसके दायरे में हैं और आए दिन नए-नए प्रकार के साइबर ठगी की शिकायतें प्राप्त होते रहती हैं द्य आज के समय में जितने टेक्नोलॉजी बढती जा रही है उतने ही साइबर अपराध की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, इसलिए सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचनी चाहिए और साइबर अपराध से बचने के तरीकों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया एवं जगह-जगह पर कैंप लगाकर आम जनता को साइबर फ्रॉड से बचाव के तरीकों के बारे में लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है सावधानी हटी दुर्घटना घटी द्य सावधान रहें और सुरक्षित रहें।

✯ **साइबर अपराध को कैसे रोका जाए?**

साइबर अपराध रोकने के लिए मजबूत और अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें, सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस को अपडेट रखें, संदिग्ध ईमेल/लिंक से बचें, सार्वजनिक वाई-फाई पर सतर्क रहें, दो-कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करें और संवेदनशील जानकारी ऑनलाइन साझा न करें; साथ ही, डेटा का नियमित बैकअप लें और किसी भी धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करें, जैसे हेल्पलाइन 1930. साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in या 1930 पर करें। सीईआरटी-इन और 14 सी निगरानी करते हैं।

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
7004408851
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

❖ **व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय :-**

☞ **मजबूत पासवर्ड :-** हर अकाउंट के लिए अलग, लंबे और जटिल पासवर्ड (अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का मिश्रण) का प्रयोग करें और उन्हें नियमित रूप से बदलें।

☞ **सॉफ्टवेयर अपडेट :-** अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप्स और एंटीवायरस को हमेशा अपडेटेड रखें।

☞ **एंटीवायरस/फायरवॉल :-** विश्वसनीय एंटीवायरस और फायरवॉल सॉफ्टवेयर का उपयोग करें और उन्हें सक्रिय रखें।

☞ **फिशिंग से बचें :-** अनजाने ईमेल, मैसेज या पॉप-अप में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें; संदिग्ध अटैचमेंट डाउनलोड न करें।

☞ **फिशिंग और धोखाधड़ी :-** निवेश स्कैम, डिजिटल अरेस्ट। आईपीसी धारा 420 के साथ आई टी एक्ट लागू।

☞ **टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन :-** जहाँ भी संभव हो, 2FA या मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) सक्षम करें।

☞ **संवेदनशील जानकारी :-** सोशल मीडिया या असुरक्षित साइटों पर अपनी निजी जानकारी (जैसे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड) साझा न करें।

☞ **डेटा बैकअप :-** अपने जरूरी डेटा का नियमित रूप से बैकअप (बाहरी ड्राइव या क्लाउड पर) लें।

☞ **सार्वजनिक Wi-Fi :-** सार्वजनिक Wi-Fi का उपयोग करते समय सावधान रहें या VPN (Virtual Private Network) का प्रयोग करें।

❖ **घटना होने पर क्या करें :-**

☞ **बैंक/कार्ड :-** वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तुरंत अपने बैंक को सूचित करें।

☞ **पासवर्ड बदलें :-** प्रभावित खातों के पासवर्ड तुरंत बदलें, खासकर ईमेल और बैंकिंग के।

☞ **रिपोर्ट करें :-** किसी भी साइबर अपराध की शिकायत संबंधित अधिकारियों (जैसे cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन 1930) को तुरंत दर्ज करें।

☞ **बच्चों की सुरक्षा :-** बच्चों को इंटरनेट के खतरों के बारे में शिक्षित करें और उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें।

आवश्यकता

अगर आप में है आत्मविश्वास और तीव्र इच्छा, तो मौका है इसे पूरा करने का....

बिहार की सबसे लोकप्रिय पत्रिका

केवल सच

और

केवल सच TIMES

को बिहार के हर जिले, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि (डोर टू डोर मार्केटिंग) एवं प्रसार के कार्य के लिए परिश्रमी एवं जुझारू युवक/युवतियों की आवश्यकता है।

योग्यताः-

जिला ब्यूरो	प्रखंड संवाददाता	पंचायत संवाददाता	विज्ञापन प्रतिनिधी
स्नात्तक उतीर्ण	स्नात्तक/इंटर	स्नात्तक/इंटर/मैट्रिक	स्नात्तक/इंटर/मैट्रिक

संपर्क करेः-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, कंकड़बाग

पटना-20, मो.- 9431073769, 9955077308

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD. · Dispersing Happiness

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.

Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008